● वर्ष-3
● अंक-88
रायपुर, मंगलवार
21 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› वकालत में कैरियर

राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री बोले- कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी

कांग्रेस की मानसिकता आतंकी: मोदी

जयपुर। राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित कर कहा कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले योद्धा कुशाल सिंह जी की धरती पर मैं आप सभी का और पूरे राजस्थान को नमस्कार करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए मैं, हमारे ओम जी सालों से संगठन का काम करते थे। कंधे पर थैला लटका कर बसों में जाना, पार्टी का काम करते थे और चुनाव प्रबंधन भी देखते थे। लेकिन कभी चुनाव में कोई हमें कहे कि आपको सभा मिलेगी, बड़े से बड़े नेता की मिलेगी तो भी हम कहते साहब हम सभा तो करेंगे। लेकिन सुबह 11 बजे मत दो, देना है तो दो बजे, तीन बजे और चार बजे दे दो। 11 बजे सुबह संगठन का काम करते हुए देखता हूं लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये पाली की ताकत, पाली के लोगों का प्यार, पाली के कार्यकर्ताओं की मेहनत। सुबह-सुबह इतनी बड़ी जनता जनार्दन, एक तरह से मैं जन सागर देख रहा हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि सभा का आयोजन छोटा पड़ गया, उसके लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। जो लोग ताप में तप रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ सभा को सुन रहे हैं। जो ताप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये ताप आपकी तपस्या को कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके उसे लौटाऊंगा। आपके लिए कल्याण योजनाएं लेकर आऊंगा और आपकी ये तपस्या, मैं प्यार से उसकी कीमत चुकाऊंगा। आपको वादा करता हूं।

भाइयों-बहनों ये पाली ऐसा है कि ये कभी पाला बदलता ही नहीं है। पाली की दूसरी ताकत भी है, पाली वालों को मालूम है कि नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, खासकर के मेरे गुजरात में जाकर देखिए कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जहां पाली वाला भाजपा झंडा लेकर न खड़ा हो। आप तमिलनाडु में किसी को जाकर पूछोगे तो कहेगा कि मैं पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है और जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली वालों की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की यह पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या-क्या कहा है, यह पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं-बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का एलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है कि राजस्थान की संस्कृति को समाप्त करना। क्या ये करने देंगे आप, ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे। एक घमंडिया गठबंधन की करतूत मान्य करेंगे।

मोदी ने कहा कि आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार होनी जरूरी है जो राजस्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले पांच साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवाद ही सबकुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टिकरण का राजनीति का असर क्या होता है इसको राजस्थान ने बीते पांच वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। आतंकी मानसिकता रखने वालों के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है।

साथियों हम सब तो भलीभांति जानते हैं कि यहां जालौर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं। भगावन की पूजा करते हैं और सब लोग वहां जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखियों महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी-कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली कि कोई सामान्य नागरिक बातचीत में भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। वे विधानसभा के सदन में बोल रहे थे। ये है घमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं।

अयोध्या में 80 हजार श्रद्धालुओं के लिए बसाई जा रही टेंट सिटी

अयोध्या। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश-विदेश से लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया माझा गुप्तार घाट में 20 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें लगभग 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम में ब्रह्मकुंड के पास भी एक टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। इसमें 35 टेंट लगेंगे, जिसमें लगभग 30 हजार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने बताया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग बिजेसी में 25 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें लगभग 25 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अलावा कार सेवकपुरम व मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जाएगी।विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समय कड़ाके की ठंड रहेगी। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। शीतकाल में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखते हुए टेंट सिटी का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए गद्दे-कंबल का भी प्रबंध हो रहा है। यहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं के लिए शौचालय व स्नान गृह के अतिरिक्त भोजन के लिए भंडारागृह व मेडिकल शिविर का भी प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडीए की ओर से जो टेंट सिटी स्थापित की जा रही है वह ठेकेदारों द्वारा निर्मित की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) ने रविवार को तमिलनाडु के कई हिस्सों में मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सफेद-खाकी वर्दी पहने आरएसएस के सदस्यों ने मार्च में हिस्सा लिया। इसके साथ-साथ कई स्थानों पर सभाएं भी आयोजित की गईं।

इंफाल एयरपोर्ट पर नजर आया यूएफओ?

■ **3 घंटे तक प्रभावित रही उड़ानें**

नईदिल्ली। मणिपुर में इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्त (यूएफओ) देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद भारतीय वायु सेना ने दो राफेल लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया। हासीमारा एयर बेस से लॉन्च किए गए राफेल को कुछ भी पता नहीं चल सका। पहला विमान बेस पर लौट आया और दूसरे को फिर से जांच करने के लिए क्षेत्र की ओर तैनात किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। भारतीय वायु सेना की पूर्वी कमान ने कहा कि उसने अपने वायु रक्षा प्रतिक्रिया तंत्र को अलर्ट कर दिया है। आईएएफ ने इंफाल हवाई अड्डे से दृश्य इनपुट के आधार पर अपने वायु रक्षा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया। इसके बाद छोटी वस्तु नहीं देखी गई।बता दें कि मणिपुर के इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर को एक अज्ञात उड़ती वस्तु (यूएफओ) दिखाई दी। इस अज्ञात वस्तु के आसमान में दिखतेही एयरपोर्ट अधिकारी हरकत में आ गए और उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया। हवाई यातायात नियंत्रक उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने मणिपुर के इम्फाल अंतर्राष्टीय हवाई अड्डे पर रनवे के करीब एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखी, जिसके कारण कई उड़ानों को अचानक डायवर्ट करना पड़ा और देरी हुई। इम्फाल हवाई यातायात नियंत्रण को दोपहर 2.30 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियंत्रण कक्ष से एटीसी टॉवर के ठीक ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखे जाने की सूचना मिली। सफेद रंग की वस्तु एटीसी टावर की छत से दिखाई दे रही थी और एयरलाइन और सीआईएसएफ कर्मियों सहित जमीन पर मौजूद लोगों ने भी इसे देखा। अज्ञात वस्तु टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर से उड़ी, एटीसी टावर के ऊपर दक्षिण की ओर चली गई और कुछ समय तक वहीं स्थिर रही। फिर यह रनवे के दक्षिण-पश्चिम की ओर चला गया, जहां यह गायब होने से पहले शाम 4.05 बजे तक रहा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने तुरंत मणिपुर की राजधानी इंफाल में नियंत्रित हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और सभी उड़ान संचालन बंद कर दिया। हवाई क्षेत्र बंद होने से लगभग 1,000 यात्री प्रभावित हुए।

मणिपुर के इंफाल अंतरराष्टीय हवाई अड्डे पर दोपहर को एक अज्ञात उड़ती वस्तु दिखाई दी। इस अज्ञात वस्तु के आसमान में दिखतेही एयरपोर्ट अधिकारी हरकत में आ गए और उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया। हवाई यातायात नियंत्रक उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने मणिपुर के इम्फाल अंतर्राष्टीय हवाई अड्डे पर रनवे के करीब एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखी, जिसके कारण कई उड़ानों को अचानक डायवर्ट करना पड़ा।

प्रमुख समाचार

भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था फेक: जयराम रमेश

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद (एमपी) और संचार के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने 4 ट्रिलियन डॉलर की कमाई की। बीजेपी के कई नेताओं ने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट साझा किया और दावा किया कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है। हालाँकि, यह दावा फर्जी साबित हुआ और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई मंत्रियों और अन्य को अपना ट्वीट हटाना पड़ा।कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब पूरा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देख रहा था। राजस्थान और तेलंगाना के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सहित मोदी सरकार के विभिन्न ढोल बजाने वाले, जैसे साथ ही पीएम के सबसे पसंदीदा बिजनेसमैन ने ट्वीट किया कि कल ही भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है।भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, तेलंगाना से जी किशन रेड्डी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और व्यवसायी गौतम अडानी उन प्रमुख लोगों में से थे। रविवार को भारत के .4 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को पार करने के बारे में ट्वीट किया था।

अनुच्छेद 370 पर सरकार ने देश के साथ किया धोखा: उमर

नईदिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूकें हैं, तो अनुच्छेद 370 के कारण हैं। अगर कश्मीर में अलग सोच रखने वाले लोग हैं, तो सिर्फ धारा 370 के कारण हैं। अगर धारा 370 हटी तो बंदूकों से राहत मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी एक हफ्ता भर भी नहीं हुआ है जब इस इलाके में मुठभेड़ हुई थी। 5 लोग मारे गए थे। सरकार ने कहा कि वे आतंकवादी थे। उनमें से 4 ने 2020 में और 5 ने 2021 में हथियार उठाए यह 2019 के बाद था।उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहने को तो आपने कहा कि 2019 के बाद वहां कोई बंदूक उठाने वाला नहीं होगा। सब संतुष्ट होंगे, सब खुश होंगे। अगर ये बात सही है तो ये 5 क्यों मर गए हैं। इन्होंने बंदूक उठाई थी। कहीं न कहीं इसमें आपकी नाकाबलियत है। कहीं न कहीं इसमें आपका धोखा है। अबदुल्ला ने कहा कि न केवल आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया आपने पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दिया। मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बस अब अमन होगा।

गिरफ्तारी संजय सिंह की याचिका पर केंद्र से जवाब

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी किया और उन्हें 11 दिसंबर से पहले अपना जवाब देने को कहा। कथित घोटाले के सिलसिले में सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।इस बीच, दिल्ली और उसके उपनगरों में हवा की गुणवत्ता रात भर में खराब हो गई, पिछले दिन मामूली सुधार हुआ था। पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में बड़ी राहत की संभावना नहीं है। सोमवार सुबह 8 बजे तक, शहर का ्त्त्ध्र गिरकर 338 हो गया, जबकि रविवार शाम 4 बजे यह 301 था। इसी तरह, गाजियाबाद (306), गुरुग्राम (239), ग्रेटर नोएडा (288), नोएडा (308), और फरीदाबाद (320) जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता में गिरावट देखी गई।

समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे पर साधा निशाना

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति और बोलने की और अधिक स्वतंत्रता देने की जरूरत है जहां उन्हें पहनावे और धर्म के आधार पर निशाना नहीं बनाया जाए। तेलंगाना में भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी लागू करने, अयोध्या में राम मंदिर और काशी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क यात्राएं आयोजित करने समेत अन्य वादों पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद के सांसद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय इस तरह की चीजों में शामिल रहती है। भाजपा ने 18 नवंबर को कहा था कि तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में यूसीसी लागू की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था।

खास पेंट के आगे फेल हो जाएंगे चीन-पाकिस्तान के रडार

नईदिल्ली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की रक्षा प्रयोगशाला ने एक रडार अवशोषक पेंट विकसित किया है जो सैन्य विमानों को अपने रडार हस्ताक्षर को कम करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें दुश्मन के रडार के खिलाफ अधिक से अधिक चुपके विकसित करने में मदद मिलेगी। कथित तौर पर पेंट का इस्तेमाल डीआरडीओ के अपने विमानों और अन्य प्लेटफार्मों पर किया जाएगा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, रडार एब्जॉर्बिंग पेंट के विकास के पीछे रक्षा प्रयोगशाला टीम के नेता डॉ नागराजन ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित पेंट का उपयोग अब तक मिग -29 लड़ाकू जेट सहित भारतीय वायु सेना के प्लेटफार्मों पर किया गया है और परिणामों को उत्साहजनक बताया है।सबसे खास बात यह है कि यह पेंट रडार की किरणों को इस तरह सोख लेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यह कौन सा विमान है। यह पेंट फाइटर प्लेन को पूरी तरह से बदल देगा। इससे युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमान की पहचान नहीं हो सकेगी. इसका इस्तेमाल मिसाइलों में भी किया जा सकता है। इससे दुश्मन यह पहचानने में असमर्थ हो जाएगा।

चुनावी वादे कितने खरे....आंकड़ों के खेल में झांकने का अवसर

के. सी. त्यागी

विधानसभा चुनावों के दौरान वादों की फेहरिस्त काफी लंबी हो चली है। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,700 या 2,900 रुपये क्विंटल के अलावा बोनस की भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पिछले दस साल में किए गए चुनावी वादे कहां तक पूरे हो पाए? नरेंद्र मोदी जैसे प्रभावी नेता और पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद दस साल का हिसाब-किताब लगाना जरूरी है। आंकड़ों के खेल से देश को भ्रमित करना भले जारी रहे, पर कोरोना के रूप में वैश्विक महामारी हो या आर्थिक मंदी का दौर, पूर्वोत्तर राज्यों में घरेलू स्तर पर बढ़ती हिंसा हो, पड़ोसी राज्यों के साथ बढ़ता सीमा विवाद या कूटनीतिक रिश्ते, देश में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या हो या किसानों की बढ़ती आत्महत्या-मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल ही दिखी है। आज भी देश को कृषि, रोजगार, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सामाजिक-असामंजस्य की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है।

वर्ष 2004-05 में कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 21 प्रतिशत था। पिछले 18 साल में यह घटकर करीब 16 फीसदी रह गया है। लेकिन खेतों में कार्यबल की संख्या में उस हिसाब से गिरावट नहीं आई है। कृषि देश में करीब 55 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती है। इस क्षेत्र में अनुमानित 26 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। यानी करीब 55-57 प्रतिशत आबादी की कृषि पर निर्भरता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान लंबे समय से संकट में है। मोदी सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसानों को उनकी खेती से लाभकारी मूल्य तो दूर, पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा। जी-20 समिट के दौरान किए गए कृषि व्यापार समझौते से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के

अनुसार, सरकार ने कई कृषि उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिससे खासकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादकों पर संकट है।

देश के 16 करोड़ किसानों पर सभी प्रकार के बैंकों का करीब 21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है-यानी प्रति किसान कर्ज 1.35 लाख रुपये है। कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की श्रेणी में वर्ष 2021 में 10,881 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 5,318 किसान थे और 5,563 खेतिहर मजदूर। उसी साल देश में जिन 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, उनमें से 42,004 दिहाड़ी मजदूर थे, जबकि 4,246 महिलाएं थीं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में अभी 23 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद खराब है। रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 से 2015-16 तक देश में गरीबी से 27.5 करोड़ लोग बाहर आए, जबकि 2015-16 से 2019-21 तक 14 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा गांवों और शहरों में विकास की खाई को भी दिखाता है। गांवों में रहने वाले 21.2 प्रतिशत लोग गरीब हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 5.5 फीसदी है।

सालाना दो करोड़ नौकरियों के वादे और अच्छे दिन के नारे ने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में ला दिया था। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 की नोटबंदी और 2017 के जीएसटी रोलआउट के दुष्प्रभावों के कारण 2018 में करीब 1.1 करोड़ नौकरियां चली गईं। इंडिया स्पेंड के विश्लेषण के मुताबिक, रोजगार के बाजार में हर साल प्रवेश करने वाले 1.2 करोड़ लोगों में से केवल 47.5 लाख लोग ही श्रम बल में शामिल होते हैं। यूपीए सरकार के दशक में गैर-कृषि क्षेत्र में सालाना 75 लाख नौकरियों का सृजन हुआ; जबकि 2013-19 की अवधि में कोविड से पहले केवल 29 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजित हुईं (सरकारी पीएलएफएस डेटा के आधार पर)। 2004 से 2019 के बीच ग्रामीण/शहरी भारत में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ी, और फिर आर्थिक और स्वास्थ्य कुप्रबंधन के कारण कोविड़ के दौरान और भी अधिक बेरोजगारी बढ़ी। वर्तमान सरकार में युवा बेरोजगारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है। दूसरी ओर, वास्तविक वेतन वृद्धि भी तेजी से धीमी हो गई है।

हाथियों का खौफ जारी, पसान व केंदई रेंज में 4 लोनरों से बढ़ा खतरा

कोरबा। जिले के वन मंडल कटघोरा व कोरबा में हाथियो का खौफ जारी है यहां के पसान व केंदई रेंज में कुल 63 की संख्या में हाथी घूम रहें है। जिनमें से 59 हाथी पनगंवा व जलके क्षेत्र में सक्रिय है जबकि दो लोनर हाथी रेंज के बनिया व तनेरा गांव में मंडरा रहे है केंदई रेंज के साल्ही पहाड़ तथा उच्चलैंगा में दो लोनर हाथियो का विचरण दल से अलग हो रहा है।

लोनर हाथियो के चार जगहों पर सक्रिय होने से क्षेत्र में खतरा बढ़ गया है। बढ़ते खतरे को देख वन विभाग विशेष सर्तकर्ता बरत रहा है। विभाग की ओर इन हाथियो की विशेष निगरानी की जा रही है। क्योकि लोनर हाथियो के दल से अलग होकर विचरण करने से खतरा बढ़ जाता है। दल में रहने से लोनर का स्वभाव शांत रहता है जबकि अलग होने पर आक्रामक हो जाते है केंदई रेंज के साल्ही पहाड़ में मौजूद लोनर ने बीति रात पहाड़ से नीचे उतर कर उत्पात मचाते हुए 9 ग्रामीणों के धान फसल को रौंद दिया वहीं पनगंवा व जलके में मौजूद हाथियो के दल ने भी आधा दर्जन किसानों की फसल को तहस-नहस किया है। इधर कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज अंतर्गत गुरमा में मौजूद 37 हाथियो का दल बीती रात बेकाबू हो गया । और गुरमा, चिरा व धनपुरी गांव में पहुंचकर 15 किसानो की फसल को उत्पात मचाते हुए मटिया मेट कर दिया। इन गांव में हाथियों द्वारा उत्पात मचाए जाने से ग्रामीणों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी आज सुबह प्रभावित गांव पहुंचे । और हाथियो द्वारा रात में किए गए हाथियों द्वारा नुकसानी का आक्लन करने के साथ रिपोर्ट तैयार की ।

दंतैल हाथी ने जमकर मचाया उत्पात

बालोद। जिले के गुरुर वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। बीती रात कई गांवों के अंदर दंतैल हाथी घुस गया और फसलों को नुकसान पहुंचाया। जिससे ग्रामीणों को दहशत में रात गुजारनी पड़ी। इस बीच वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से घरों में रहने की अपील की है। दंतैल हाथी को लेकर वन विभाग ने ग्राम जगतरा, सोहतरा, बिच्छीबाहरा, खैरडीगी, धनापुरी, ओड़ेनाडीह, डोकला आदि गांवों को अलर्ट किया है और जंगल नहीं जाने की अपील की है। वर्तमान में हाथी जंगली भेजा गांव के जंगल में उपस्थित है।

कलेक्टर-एसपी ने किया धान खरीदी केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

बलौदाबाजार। कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने आज बलौदाबाजार और पलारी विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने बलौदाबाजार के ग्राम सकरी, पलारी के ग्राम पंचायत अमेरा और नगर पंचायत पलारी के धान खरीदी केन्द्रों में धान बेचने पहुंचे किसानों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंजी,बारदाना रजिस्टर,टोकन रजिस्टर की बारिकी से जांच की। इसके साथ ही ढेरी में लगाए हुए धान को पॉस मशीन के जरिये आर्द्रता को मापा गया। जांच के दौरान धान की गुणवत्ता सही पाई गई। इस दौरान कलेक्टर को कही कही किसानों से सूखत के नाम से किसानों से अधिक धान खरीदी और निर्धारित तय सीमा में नमी धान की शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होने सभी अधिकारियों एवं प्रबंधको को दो टूक कहा कि किसी भी स्थिती में किसानों से सूखत के नाम से अधिक धान की तोलाई ना करे ना ही तय सीमा से अधिक नमी वाले धान की खरीदी की जाएं इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र प्रभारी से कहा कि किसान कड़ी मेहनत कर धान उत्पादन करता है। किसान की मेहनत का वाजिब दाम मिले और उनके काम का सम्मान हो, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन केंद्र में छाया और बैठक व्यवस्था अनिवार्य रूप से बनाए रखें। एक दिन में जितने किसानों से धान की खरीदी हो सके, उतने ही किसानों को धान खरीदी केंद्र में बुलाया जाए। ऐसा ना हो कि कोई किसान धान बेचने के लिए आए और उसे अनावश्यक रूप से अधिक समय तक रूकना पड़े।

कलेक्टर कुमार ने मौके पर किसानों, फड़ प्रभारी, मजदूरों अन्य ग्रामवासीयों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम अमेरा निवासी प्रदीप कुमार ने कलेक्टर कुमार को बताया कि मुझे धान बेचने में किसी

भी तरह की परेशानी नहीं हुई। सकरी धान खरीदी में किसान ग्राम सकरी धनी राम साहू ने बताया कि आज मैंने 900 कट्टा धान सकरी खरीदी केन्द्र में बेचा हूं। इसी तरह पलारी धान खरीदी के प्रबंधक ने बताया कि लगभग 800 किसान समिति में पंजीयन है। जिसमें से अभी तक 60 किसानो ने अपने धान बेचे हैं। उक्त निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर नम्रता चौबे,खाद्य अधिकारी विमल कुमार दुबे,नोडल अधिकारी शर्मा, डीएमओ निधि शशांक दुबे और डीआरसीएस गौड़ सहित संबंधित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 6 हजार 328 किसानों से 21 हजार 282 में। टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिसके तहत 19 हजार 591 में।टन मोटा, 718 मे।टन पतला, 973 मे।।टन सरना शामिल है। इसके एवज में लगभग 43 करोड़ रूपये का भुगतान आंनलाईन माध्यम से किया जा चुका है। अभी तक 4 हजार 192 में।टन डीओ जारी की जा चुकी है। लगभग मिलर द्वारा 1 हजार 97 में।टन का उठाव भी किया चुका है। गौरतलब है कि जिले में 1 लाख 62 हजार 534 किसान पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार फ्लेग मार्च एवं पेट्रोलिंग से निर्भीकता से हुई सर्वाधिक मतदान

धमतरी। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर आरिफएच. शेख के दिशानिर्देश पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रशांत ठाकुर के कुशल नेतृत्व में पिछले साल के तुलना में इस वर्ष एवं आचार संहिता के दौरान सर्वाधिक कुल 3943 लोगों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। और इन प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों से सामाजिक तत्वों और गड़बड़ी करने वाले लोगों में एक कड़ा संदेश गया कि चुनाव प्रक्रियाओं में अगर वह बदमाशी करते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव के पूर्व तक असामाजिक तत्वों व गुंडा बदमाशों की कड़ी निगरानी की गई और थानावार फ्लेग मार्च निकाली गई। एवं पॉच व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जिला बदर के प्रकरण बनाए गए और जिसमें से चार व्यक्तियों को जिला बदर किया गया।

आचार संहिता दौरान वारंटी को प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दूसरे प्रदेशों से भी लाकर कोर्ट में पेश किया गया। विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 को निष्पक्ष,निर्भिग्य एवं

शांतिपूर्ण मतदान हेतु वर्ष 2023 जनवरी माह से अब तक 74 लोगों पर 110 सीआरपीसी.के तहत कार्यवाही कि गई है तथा 3410 लोगों के ऊपर 107,116 कि कार्यवाही कि गई है एवं 151 सीआरपीसी के तहत 441लोगों के उपर कार्यवाही की गई है। इस माह आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए धमतरी पुलिस द्वारा सर्वाधिक प्रतिबंधक कार्यवाही किया गया है कुल में 3943 लोगों पर कुल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाऊंड ओवर किया गया है। छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 (जिला बदर)के तहत 05 बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण पेश किया गया था जिसमें 04 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई है। इस पूरे वर्ष में अब तक कुल 3943 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है, सकड़ों लोग जेल भेजें गए। 2022 में पूरे वर्ष में कुल 3219 लोगो पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और 2021 में 2314 लोगो पर कार्यवाहियां हुई थी। इन कार्यवाहियों का सीधा असर चुनाव के दौरान देखने को मिला, पूरे जिले में चुनाव के दिन एक भी बड़ी हिंसा या वाद-विवाद के प्रकरणों में चुनाव के दिन कोई एफ्आईआर दर्ज नहीं हुई। लगातार पुलिस टीम द्वारा की गई पेट्रोलिंग और पुलिस टीम द्वारा शिकायत स्थल पर त्वरित पहुंचने से कही भी बड़ा विवाद नहीं हुआ। धमतरी पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब एवं नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कि गई कार्यवाही। जिसके तहत इस साल जनवरी माह से अवैध नशा और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्यवाहियों से नशे के व्यापार पर अंकुश लगा, साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हुडदंग करने वाले लोगों पर लगातार कार्यवाहियों से भी कड़ा संदेश गया।

कांग्रेस ने पूर्व महिला शहर अध्यक्ष समेत 3 नेता को किया निष्कासित

- **बागियों को बाहर का रास्ता, पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई**

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में बगावत करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पार्टी ने जगदलपुर में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ गतिविधियों में काम करने के आरोप में तीन कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की है। जिसमें पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज, विक्रम शर्मा और कुक्की झारी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जयसवाल और स्थानीय संगठन के पदाधिकारी ने आला कमान से भीतरघातियों की शिकायत की थी। आला कमान के निर्देश पर जगदलपुर में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने निष्कासन की कार्रवाई करते हुए 3 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है।

गौरतलब है कि पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज ने डेढ़ वर्ष पहले अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था लेकिन पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। चुनाव के दौरान भी उन्हें मान मनोबल का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी किरण देव का प्रचार किया और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने निष्कासन की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जगदलपुर में विक्रम शर्मा और कुक्की झारी पर भी पार्टी विरोधी गतिविधि करने पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है।

ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग में पूजा की कवासी लखमा ने

जगदलपुर। मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थल के प्रवास पर निकले छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने रविवार को ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने बस्तर तथा छत्तीसगढ़ में सुख, शांति की कामना की, इस दौरान पत्नी साथ रही। उन्होंने शिवालय में दर्शन करने कतार में खड़े लोगों का अभिवादन कर सबकी मनोकामना पूरी होने की भगवान शंकर से प्रार्थना की।

दो युवतियों ने महिला पर डंडे और लोहे के तवा से किया जानलेवा हमला

रायगढ़। ग्राम ननसिया में घरेलू विवाद को लेकर दो सगी बहनों ने परिवार के एक व्यक्ति के साथ अपनी भाभी को हाथ मुक्का, डंडा और तवा से मारकर गंभीर चोट पहुंचाया। घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में थाना जूटमिल ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया वहीं कुछ की तलाश में जुटी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला बुधयारिन बाई (25 साल) के पति केशव महंत निवासी ननसिया रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि पूर्व में उसकी बहन मधु सिदार, उसका पति राम सिंह सिदार और रितु महंत गांव ननसिया में रहते थे। उसकी पत्नी बुधियारिन का उसकी मां, दीदी मधु और बहन रीतू के बीच घरेलू झगड़ा विवाद होता था। इसी झगड़ा विवाद को लेकर 16 नवंबर के शाम मधु, रितु और मधु का पति राम सिंह घर अंदर घुसकर उसकी पत्नी बुधियारिन बाई से पूर्व झगड़ा विवाद रंजिश को लेकर गाली गलौज मारपीट करते हुए हाथ मुक्का और डंडा, लोहे के तवा से मारपीट की। इससे बुधियारिन बाई को गंभीर चोटे आई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में आरोपियों के विरुद्ध धारा 450, 307, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर घटना के बाद से फरार हुए महिला आरोपी मधु सिदार पति रामसिंह सिदार उम्र 33 साल निवासी अमलीभौना इंदिरा आवास सोनमुडा व रितु महंत पिता हेमलाल महंत उम्र 22 साल निवासी ननसिया हाल मुकाम अमलीभौना इंदिरा आवास सोनमुडा को जूटमिल पुलिस द्वारा गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मामले में एक आरोपी राम सिंह सिदार फरार है। फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

गिरौला कैंप में तेंदुए ने दिया चार शावकों को जन्म

जगदलपुर। बस्तर जिले के गिरौला में स्थित रक्षा मंत्रालय (डीफेंस रिसर्च एंड डेवल्पमेंट ऑर्गोनाइजेशन) के क्षेत्र में मादा तेंदुए ने चार शावको को जन्म दिया है, जिसके चलते दिन और रात सुरक्षा में लगे रक्षा कर्मी दहशत जदा है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए सुरक्षा कर्मियों से सावधानी बरतने को कहा है। वन विभाग इन शावकों को मादा सहित अन्यंत्र स्थान पर ले जाने की जुगत में है। डिफेंस के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मादा तेंदुआ घने वन क्षेत्र में बने गिरौल कैंप के शिविर में नजर आ रही थी जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग के अफसरों को दी थी। सूचना मिलने पर वन विभाग के एसडीओ ने संभावित क्षेत्र में पिंजरा की भी व्यवस्था की थी ताकि मादा तेंदुआ पिंजरे में आ सकें लेकिन मादा तेंदुआ द्वारा चार शावकों को जन्त दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने उस स्थान से पिंजरे को हटा लिया है। वन अधिकारियों का कहना है कि रात्रि पाली में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों को अधिक चौकस रहने की आवश्यकता है।

ठंड ने दी दस्तक, प्रवासी पक्षी लौटने लगे अपने देश

कोरबा। ठंड की दस्तक के साथ ही श्रीलंका सहित कई देशों से आने वाले पक्षियों का प्रवास काल कनकी में पूरा हो चुका है। अब वे अपने बच्चों के साथ मीलों का सफर पूरा कर स्वदेश लौटने लगे हैं। दशकों से यह खास किस्म के पक्षी घोंगिल ओपनबिल्ड स्टार्क जिले के कनकेश्वर धाम को अपने प्रवास का सबसे प्रिय स्थान बना लिया है। वे यहां प्रजनन के लिए आते हैं। पक्षियों का आगमन जून महीने में होता है। यह वह माह होती है जब शिव की आराधना के पवित्र माह सावन की भी शुरूआत होती है। भगवान शिव की आराधना के लिए प्रख्यात कनकेश्वर धाम में पक्षियों का आगमन शिव की आराधना से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण इन पक्षियों को आस्था से जोड़कर देखते हैं। बरसात की शुरूआत में इनका आगमन होने के करण इन्हें मानसून का सूचक भी माना जाता है। अब ठंड की शुरुआत होते ही पक्षी वापस लौटने लगे हैं। यह अपने घोसले इमली, बरगद ,पीपल,बबूल व बांस के पेड़ों पर बनाते हैं। स्टार्क पक्षी 10 से 20 हजार की संख्या तक अपने घोंसले बनाते हैं।

दो ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

बलरामपुर। जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान दो ट्रक से बड़ी मात्रा में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री जब्त किया है। जब्त विस्फोटक सामग्री और दो ट्रक की कीमत लगभग 83 लाख बताई जा रही है। यह मामला बलंगी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, वाहन चेकिंग के दौरान बलंगी पुलिस ने दो ट्रक से ऑप्टिमेक्स प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट 63 टन विस्फोटक सामग्री जब्त किया है। साथ ही परिवहन कार्य में लगे दो ट्रक को भी जब्त किया। बताया जा रहा है यह कार्रवाई परिवहन शर्तों के उल्लंघन करने पर की गई है। जब्त विस्फोटक और ट्रक सहित सामग्री की कीमत 83 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री परिवहन करने के वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।

एक साथ लगभग 20 दुकानों के टूटे ताले और शटर

महासमुंद। जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। चुनावी ड्यूटी में व्यस्त पुलिस का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बसना और सांकरा में बीती रात लगभग 20 दुकानों में सेंधमारी की है। एक साथ टूटे दुकानों के ताले और शटर से इलाके में हड़कंप मच गया है। अज्ञात चोरों लाखों रुपये नगदी और सामान साफ किया है। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार, महासमुंद के बसना शहर में 16 से 17 दुकानों में एक साथ चोरों ने सेंधमारी की है। अज्ञात चोर बीती रात किसी दुकानों के ताला तोड़ा तो किसी के सटर तोड़कर चोरी की। बसना शहर के जनपद पंचायत से लेकर बिजली आफीस तक के दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है। घटना में लाखों रूपये नगदी और सामानों की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। चार से पांच युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उसमें होटल, फैसी स्टोर्स, किराना, हार्डवेयर जैसे दुकान शामिल हैं।

पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, कोई जनहानि नहीं

कोरबा। कोरबा में एक मालगाड़ी डिरेल हो गया है। गाड़ी के पीछे लगी बोगी के करीब चार पहिए पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुआ। इसके बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच कर टीम के साथ मालगाड़ी को पटरी पर लाने जुट गए। सूत्रों ने बताया कि कोरबा के जिले में मालगाड़ी के पीछे के चार चक्के पटरी से उतर गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने इस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाया जिसमें ट्रैक में अधिक मात्रा में कोल डस्ट जमा होने के कारण घटना होने की बात सामने आई है। साथ ही प्रबंधन के द्वारा समय पर देखरेख नहीं किए जाने के कारण घटना होने की बात कही जा रही है। इस पूरी घटना के बाद पटरी से उतरे डिब्बों का मरम्मत कार्य शुरू हो चुका है।

सरगुजा में उगते सूर्य को अर्घ्य देने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़

सरगुजा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने सरगुजा के छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी हैं। सुबह 3 बजे से ही लोगों का घाटों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पहले रविवार शाम को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आज छठ पर्व का समापन हो जाएगा।

शहर के प्रमुख छठ घाट शंकर घाट, मौलवी बांध, मैरिन ड्राइव तालाब, गोधनपुर तालाब, सत्तीपारा तालाब, जेलपारा तालाब, शिवधारी तालाब, महामाया तालाब, खैरबार नहरपारा, घुनघुट्टा बांध सहित सभी घाटों पर छठ व्रतियों और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर लोग अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं।

छठ मइया के भजनों और जय जयकारों से गूंज उठे घाट छठ पूजा के लिए कई श्रद्धालु गाड़ियों से घाट पहुंचे तो कई व्रती और श्रद्धालु रंग-बिरंगे नए परिधानों में गाजे बाजे के साथ पारंपरिक छठ गीत गाते हुए पैदल ही घाटों तक पहुंचे। छठ गीतों से पूरा शहर गुंजायमान होता रहा। व्रतियों और परिजन के

रैला के बीच कई व्रती महिला-पुरुष अपने घर से छठ घाट तक दण्डवत करते हुए भी पहुंचे।

शहर से लगे घुनघुट्टा खर्रा घाट पर 25000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 1000 छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना की। रविवार को घुनघुट्टा श्याम सेवा समिति सोहगा करजी की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। आयोजन समिति ने गंगा आरती का भी आयोजन किया। बनारस से आई टीम ने सूर्यास्त होने के बाद गंगा आरती की जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। गंगा आरती का भव्य नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आयोजन समिति ने छठ घाट किनारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले का प्रसारण भी एलईडी के माध्यम से किया। ऐसे में दर्शक पूजा अर्चना के बाद वर्ल्ड कप मैच को लेकर बेहद रोमांचित नजर आए।

रामानुजगंज छठ घाट पर महिला की बिगड़ी तबीयत

बलरामपुर। छठ महापर्व के आखिर दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्रती महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते कुछ ही देर में महिला बेहोश होकर गिर गई।

घटना राम मंदिर छठ घाट की है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने हजारों लोग घाट पर तड़के सुबह से पहुंचे थे। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सभी वापस लौटने लगे। इसी दौरान महिला अचानक गिर गई। महिला के साथ आए परिजन घबरा गए। वहां मौजूद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों की मदद से तुरंत महिला को रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत नहाय खाय के साथ शुरू होती है। इस दिन लौकी भात खाकर व्रती अपनी व्रत शुरू करते हैं। इसके दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती नए चावल, नया गुड़ और गाय के दूध से खीर बनाते हैं, इसके साथ ही नए गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। इस दिन दिनभर व्रत कर शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद से व्रती का 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। जो उगते सूर्य को अर्घ्य देकर खत्म होता है। रामानुजगंज में बेहोश हुई महिला भी छठ व्रती होने के कारण 36 घंटे से निर्जला उपवास पर थी, इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि डीहाईड्रेशन के कारण महिला की तबीयत खराब हुई होगी। फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है।

500 मेगावाट क्षमता की दो नंबर इकाई में तकनीकी खराबी आने से बंद

कोरबा। राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों की इकाइयों में खराबी का सिलसिला जारी है। मड़वा संयंत्र की 500 मेगावाट क्षमता की दो नंबर इकाई में तकनीकी खराबी आने से बंद करना पड़ा है। इसके पहले की हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम की 210 मेगावाट क्षमता की तीन नंबर इकाई में भी खराबी आई थी, जिसे बंद करने के बाद मेंटेनेंस कार्य किया गया। इस यूनिट को सुधार कार्य के बाद चालू किया गया, तब उत्पादन शुरू हो सका और वर्तमान में 150 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। उधर मड़वा संयंत्र की बंद दो नंबर इकाई का भी मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही यूनिट को परिचालन में ले लिया जाएगा। ठंड बढ़ने की वजह से राज्य में बिजली की मांग घट कर पीक अवर्स में 3800 मेगावाट के करीब हो गई है। वहीं उपलब्धता 3986 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन कंपनी के एचटीपीपी से 1340 मेगावाट के स्थान पर 1082, डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र से 500 के स्थान पर 464 मेगावाट, एक हजार मेगावाट के अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा से 426 मेगावाट तथा बांगो जल विद्युत संयंत्र से 120 के स्थान पर 39 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। इस तरह कंपनी से कुल 1992 मेगावाट बिजली रही। जबकि राज्य के सीपीपी व आइपीपी से बिजली लेने पर कुल उपलब्धता 2051 मेगावाट रही।

संक्षिप्त समाचार

जिला प्रशासन की पहल को निर्वाचन आयोग ने सराहा

रायपुर। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर उत्तर विधानसभा में चुनाव का दायित्व महिलाओं को सौंपे जाने के अभिनव पहल को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए जिला निर्वाचन आयोग को बधाई दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस पहल का स्वागत करते हुए अपने अधिकृत फेसबुक पर भी इसे पोस्ट किया हैं।

जैतु साव मठ में आज मनाया जायेगा आंवला नवमी

रायपुर। जैतु साव मठ पुरानी बस्ती में कल 21नवंबर को दोपहर 12 बजे आंवला नवमी पर विधिवत पूजन किया जाएगा, इस मौके पर भगवान श्री को चांदी के सिंहासन में विराजमान कराया जाएगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवली नवमी का पर्व मनाया जाता है, इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख-शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति ने मनाया दीपावली मिलन समारोह

रायपुर। ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन व्यास विद्यापीठ सभागृह कैलाशपुरी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परस राम वोहरा एवं विशिष्ट अतिथि आनद व्यास, भारती अवतार शर्मा, सविता शर्मा एवं सुनीता तिवारी थी। सम्मेलन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने संगठन के उद्देश्य एवं पूर्व में किए गए समाज एवं सनातन धर्म के उत्थान हेतु किए गए कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए आगामी 18 दिसंबर को विप्र भवन में आयोजित कार्यक्रम अविवाहित युवक युवती एवं कात्यायनी तथा परित्यकता परिचय सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित सभी सदस्यों से कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी तिवारी ,डॉक्टर एस के शर्मा,राजकुमार व्यास, सविता शर्मा, सुनीता तिवारी, भारती अवतार शर्मा, सुभद्रा तिवारी, मुक्ता तिवारी, पारुल मिश्रा, मधु मिश्रा, प्रीति झा, शोभा तिवारी, करुणा दुबे, अवधेश धर दीवान, अश्वनी मिश्रा, के के शुक्ला, संजय तिवारी, अशीष तिवारी, बबिता तिवारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफल संचालन राजकुमार व्यास एवं आभार प्रदर्शन पारुल मिश्रा ने किया। उपरोक्त जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी कान्हा तिवारी ने दी।

देवउठनी के साथ मांगलिक कार्यक्रम हो जाएंगे शुरू

रायपुर। 23 नवंबर गुरूवार को देवउठनी एकादशी जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी योगनिद्रा से जाग जाएंगे। इसके साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएंगे। अंचल में इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को थी। उसके बाद से शहनाईयों की गूंज बंद हो गई थी जो अभी तक जारी है। विवाह वाले एवं शुभ कार्य करने वाले परिवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि देवउठनी एकादशी के साथ ही वैवाहिक मुहूर्त शुरू हो जाएंगे और शहनाइयां बनजे लगेंगी। हालांकि इस वर्ष नवंबर में शादी के मात्र 5 मुहूर्त है और दिसंबर में 7 है। इस साल 12 दिन मुहूर्त बचे है जिसमें अधिकांश दिनों बड़ी संख्या में शादियॉ होगी। इसकी हलचल शुरू हो गई है हर वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष गुरूवार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11 बजकर 03 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 नवंबर को 09 बजकर 01 मिनट पर समाप्त होगी। इसके अगले 24 नवंबर को तुलसी विवाह है। इस दिन से विवाह का लग्न शुरू हो जाता है।

चुनाव के बाद एक मंच पर दिखे रमन सिंह-भूपेश बघेल

■ **बृजमोहन-ढेबर की हंसी-ठिठोली तो मंच से उतरकर चले गए मूणत**

रायपुर। रायपुर में सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा हर्षोल्लसास के साथ मनाया गया। इस दौरान बने दो मंच में से एक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही तो दूसरे मंच पर राजनीतिक संगम की बयार देखने को मिली। दरअसल, छठ पूजा के दौरान राजीनितक दलों के नेताओं ने न सिर्फ मंच साझा किया बल्कि चेहरे पर मुस्कान बिखेरे एक दूसरे से बातचीत के साथ ही जमकर हंसी ठिठोली भी की। चुनाव के बाद पहली बार रायपुरा के महादेव घाट में छठ पूजा आयोजन समिति के मंच पर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह एक साथ दिखे। इसके अलावा रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर मेयर एजाज ढेबर और कांग्रेस नेता आरपी सिंह भक्तिमय माहौल में बातचीत करते दिखे।

दूसरी और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय और पूर्व विधायक राजेश मूणत एक दूसरे से कतराते दिखे। जब विकास उपाध्याय ने मंच से भाषण देना शुरू किया तो राजेश मूणत मंच से उतरकर दूसरे कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। चुनाव खत्म होने के बावजूद दोनों नेताओं में राजनीतिक तल्खी दिखी। पूर्व सीएम रमन सिंह मंच पर भाषण दे रहे थे तो इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। भाषण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खड़े होकर पूर्व सीएम रमन का अभिवादन किया फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान मंच पर बृजमोहन अग्रवाल और एजाज ढेबर की हंसी ठिठोली भी देखने को मिली।

मंच पर आयोजन समिति के कार्यकर्ता सीएम का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान काफी देर तक रमन सिंह बैठे रहे। हालांकि सीएम और पूर्व सीएम ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, लेकिन हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन जरूर किया। भूपेश बघेल के भाषण से पहले ही रमन सिंह मंच से उतरकार दूसरे कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छठ पूजा आयोजन समिति ने सभी को न्यौता दिया था। छठी मैया का पर्व सबके लिए है। इसलिए इसमें राजनीतिक दल की कोई सीमा नहीं होती। सभी लोग दल से ऊपर उठकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

जब बृजमोहन अग्रवाल पर हुआ था हमला

हाल ही में विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर मौदहापारा में हमला हुआ था , तो उन्होंने उस दौरान इस हमले के लिए मेयर एजाज ढेबर और उनके उनके बड़े भाई अनवर ढेबर पर आरोप लगाया था। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास पर आरोप लगाते हुए कहा था कि महंत के गुंडों ने हार के डर से उन पर हमला किया है पर छठ पूजा में सारे आरोप दूर कर मेयर ढेबर और बृजमोहन एक दूसरे से बातचीत और हंसी मजाक करते दिखे। इसलिए कह सकते हैं कि राजनीति में कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं होता। इस मामले में मुहावरा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, सही और सटीक बैठता है।

बागी न बिगाड़ दे खेल,कुछ सीटें तो हैं जहां दावेदारों में है घबराहट

रायपुर। 3 दिसंबर को परिणाम का इंतजार तो है लेकिन इससे पहले जीत हार को लेकर कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। पार्टी के छोटे बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि जीत तय है चाहे वे कांग्रेस के हो या भाजपा के लेकिन इस बात पर जाकर ठिठक जा रहे हैं कि कितनी सीट पा रहे हैं और कितनी सीट पर गच्चा खा रहे हैं। कुछ सीटों पर बागी प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ रहे हैं यह भी सौ फीसदी सच है। जिन्हे कमतर आंकना पार्टी की भूल होगी इसलिए भीतरखाने यहां से चुनाव लडने् वाले भी कहीं न कहीं घबराये हुए हैं कि कहीं जीत छिन न जाए? इसके लिए इंतजार करना होगा परिणाम आने के दिन तक,तब तक कयास लगने दीजिए। यह भी जान लें कि किन सीटों पर ऐसे बागी थे जो समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

कांग्रेस के बागी--जशपुर विधानसभा सीट से प्रदीप खेस कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के खिलाफ, सक्ती विधानसभा अनुभव तिवारी प्रत्याशी डा. चरणदास महंत के खिलाफ, जैजैपुर से टेकचंद्र चंद्रा प्रत्याशी बालेश्वर साहू के खिलाफ, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन शेषराज हरबंश के खिलाफ, पाली-तानाखार से छत्रपाल सिंह दुलेश्वरी सिदार के खिलाफ, लोरमी से सागर सिंह बैस थानेश्वर साहू के खिलाफ, मुंगेली से रूपलाल कोसरे संजीत बनर्जी के खिलाफ, सरायपाली से विधायक किस्मतलाल नंद चातूरी नंद के खिलाफ, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा कुलदीप जुनेजा के खिलाफ, धमतरी से लोकेश्वरी साहू ओंकार साहू के खिलाफ, बालोद से मीना साहू संगीता सिन्हा के खिलाफ और कसडोल से गोरेलाल साहू संदीप साहू के खिलाफ चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

भाजपा के बागी--भटगांव विधानसभा सीट से राम बाई देवांगन भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े के खिलाफ, जशपुर से शिव भगत रायमुनि भगत के खिलाफ, रायगढ़ से गोपिका गुप्ता ओपी चौधरी के खिलाफ, मस्तुरी से चांदनी भारद्वाज डा. कृष्णमूर्ति बांधी के खिलाफ, वैशालीनगर से जेपी यादव और संगीता केतन शाह दोनों प्रत्याशी रिकेश सेन के खिलाफ, गुंडरदेही से आरके राय वीरेंद्र साहू के खिलाफ, रायपुर उत्तर से सावित्री जगत पुरंदर मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ा है।

सुबह के सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व का समापन

रायपुर। नहाय खाएगी परंपरा से शुरु हुआ चार दिन का छठ पर्व सोमवार को पौफटने से पूर्व महिलाओं द्वारा सूर्य को दिए गए अर्ध्य के साथ ही संपन्न हो गया। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में छठ पर्व का नजारा तालाबों के किनारे देखते ही बनता था। राजधानी रायपुर के महादेवघाट, व्यास तालाब सहित शहर से लगे समीपस्थ ग्रामों के तालाबों में नगर निगम व जिला पंचायत प्रशासन के द्वारा छठ पर्व को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि पूजा करने वाले व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तालाबों को सजाया गया था जो कि आकर्षण का केंद्र रहे, रविवार की शाम अस्त हो रहे सूर्य को जहां पूजा-अर्चना कर अर्ध्य दिया गया वहीं सोमवार की सुबह तालाबों में पूरा मेला लगा था जहां उगते सूर्य को अर्ध्य दिया गया और इसके बाद प्रसाद वितरण के साथ ही यह चार दिवसीय छठ पर्व का समापन हुआ। छठ पर्व की पूजा में बिहार वासियों के अलावा स्थानीय महिलाआएं सहित नेतागण भी शामिल हुए जिन्होंने इस पर्व की शुभकामनाएं दी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बढ़ती दिलचस्पी या कुछ और!

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जीत के लिए कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कई घोषणाएं की। सभी राजनीतिक दलों ने हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। सभी पार्टियों ने खास फोकस महिलाओं पर रखा। भाजपा ने महिलाओं को साल में 12000 रुपये सालाना देने की घोषणा की तो कांग्रेस ने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए साल में 15000 रुपये देने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने का वचन छत्तीसगढ़ की महिला महतारियों को दिया। इन घोषणाओं का असर भी चुनाव में दिखा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हुए पुरुषों से ज्यादा वोट डाले।

छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को हुए। दोनों चरणों का मतदान प्रतिशत देखने पर इस बात का पता चला कि वोट डालने में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान को लेकर जागरूक हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने बढ़चढ़ कर मतदान किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पांचों संभाग की कई सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। सरगुजा संभाग की भरतपुर-सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव। बिलासपुर संभाग की लैलूंगा, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, पालीतानाखार, जैजैपुर, मरवाही, रायपुर संभाग के सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, राजिम, बिंद्रानवागढ़, सिहावा, डोंडीलोहारा, गुंडरदेही, संजारी-बालोद, धमतरी है। दुर्ग संभाग के दुर्ग शहर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहलामानपुर, बस्तर संभाग के भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट,दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोट, पुरुष वोटों की संख्या में ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में हुए मतदान में कुल 1 करोड़ 55 लाख 61 हजार 460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमे 77 लाख 48 हजार 612 पुरुष मतदाता और 78 लाख 12 हजार 631 महिला मतदाता शामिल हैं। इस तरह 64 हजार महिलाओं मतदाताओं ने ज्यादा वोट डाले।

बस्तर संभाग के लगभग सभी जिलों में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है जिससे महिलाओं का वोटिंग परसेंट हमेशा ज्यादा रहता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में दूसरे संभागों की कई सीटों में महिला वोट बैंक बढ़ा है। इसके पीछे एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस बार राजनीतिक दलों फिर चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा या आप सभी ने महिलाओं को टारगेट में लेते हुए उनसे जुड़े कई वादे किए। जिसका असर कही ना कही महिलाओं पर पड़ा।

स्वच्छ छवि और संघ की पृष्ठभूमि ने छत्तीसगढ़ भाजपा में बढ़ाया अरुण साव का कद

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव (55) बिलासपुर से सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोरमी से टिकट दिया। अरुण साव को वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रियों की जब लिस्ट बन रही थी, तब ऐसी चर्चा थी कि अरुण साव को भी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। बाद में उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बेहद साफ-सुथरी छवि के नेता अरुण साव को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। संघ परिवार से उनके परिवार का पुराना नाता रहा है। अरुण साव के पिता अभयराम साव जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक थे। यही वजह रही कि वर्ष 2014 में बिलासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले लखनलाल साहू की जगह अरुण साव को बीजेपी ने वर्ष 2019 में अपना उम्मीदवार बनाया। बाद में जब विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, तो उनकी जगह अरुण साव को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसकी भी बड़ी वजह यही रही कि वह संघ की पृष्ठभूमि से हैं और उनकी छवि बेदाग है। 1.66 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर कोई लोन नहीं है।

अरुण साव छत्तीसगढ़ के उस साहू समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो राज्य में बहुसंख्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के बड़े नेता भूपेश बघेल की काट के रूप में इसी समाज के नेता अरुण साव को आगे किया गया। बता दें कि अरुण साव से पहले वर्ष 2014 में लखनलाल साहू ने बिलासपुर लोकसभा सीट 1.76 मतों के अंतर से जीता था। बावजूद इसके उनका टिकट काटकर अरुण साव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अरुण साव ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य के रूप में की। छात्र जीवन में ही एबीवीपी से जुड़ गए। वर्ष 1990 से 1995 तक वह एबीवीपी की मुंगेली इकाई के अध्यक्ष रहे। बाद में राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य बनाए गए।

मुंगेली से स्नातक की पढ़ाई करने वाले अरुण साव ने कानून (लॉ) की पढ़ाई भी की है। लॉ की डिग्री उन्होंने बिलासपुर से ली। वर्ष 1996 में अरुण साव को भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के जिलाध्यक्ष बने। तत्कालीन विधायक अमर अग्रवाल के साथ महासचिव भी रहे। बीजेपी ने अरुण साव को इस बार लोरमी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। लोरमी में कांग्रेस ने थानेश्वर साहू को मैदान में उतारा है, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने सागर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। एक और क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी लोरमी में अपना उम्मीदवार दिया है। जीजीपी की ओर से संतोष कैवर्त यहां से भाग्य आजमा रहे हैं।

लोरमी विधानसभा सीट पर वर्ष 2018 में अजित जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के धर्मजीत सिंह ने जीत दर्ज की थी। धर्मजीत ने बीजेपी के टोखन साहू को 25,553 मतों के अंतर से पराजित किया था। इस बार जेसीसी (जे) ने सागर सिंह ठाकुर को उतारा है, जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है। 46 साल के सागर 1.73 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। 27,21,290 रुपए की उनकी देनदारी भी है। वहीं, कांग्रेस के थानेश्वर साहू 57 साल के हैं। ग्रेजुएट हैं। 4.73 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी संपत्ति है। 11.32 लाख रुपए की देनदारी भी है। थानेश्वर ने बताया है कि उनके खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।

लोरमी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां 68.25 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि लोरमी विधानसभा सीट पर कुल 2,28,397 वोटर थे, जिसमें 1,16,043 पुरुष, 1,12,348 महिला और 6 थर्ड जेंडर वोटर थे। इनमें से 79,102 पुरुष, 76,768 महिला और 2 थर्ड जेंडर वोटर समेत कुल 1,55,872 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की बादशाहत यहां बनी रहती है या किसी और पार्टी को यहां जीत मिलती है। मतगणना तीन दिसंबर को होगा।

सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने कर दिया है तय: केदार

■ **उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर घमासान, बाबा तो अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 होने के बाद परिणाम को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज है। राजनीतिक दल अपने-अपने जीत एक दावा कर रहे हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव (ञ्जस् स्ढ्ढठ्ठद्दद्धस्रद्गश) के अगले चुनाव नहीं लड़ने की बात पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बयान दिया है। टीएस सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर भी तंज कसा है।

टीएस सिंह देव के सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि टीएस सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छग से उखाड़ के फेंक रहे हैं। बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे नहीं, बाबा कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं। हम चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे साथ रहे। भाजपा की सरकार बन रही हैं। अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने मे आनंद आता हैं।

कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर केदार गुप्ता ने कहा कि हमलोग तो देख रहे की कांग्रेस में कितना अंतर्कलह है। पार्टी कई टुकड़ों में बट चुकी है। मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छग का एक्जिट पोल है। जो बता रहा कि कांग्रेसी को जनता ने ठुकरा दिया है। ये आपस में भी लड़ हैं। इनका सर्वनाश, सत्यानाश तय हैं।

बीजेपी विपक्ष में हैं लेकिन आजतक कोई गंभीर शिकायत नहीं आई। कुछ शिकायत आई तो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। कांग्रेस में तो चुनाव के बाद अभी परिणाम नहीं आए हैं सिर फुटव्वल हैं।

50 सीटों पर महिला के अधिक वोट पर कांग्रेस के बयान पर केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिला और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, नारियों के साथ लगातार सामुहिक बलात्कार की घटनाये हुई। महिलाएं तनाव में थी, गुस्से में थी,शराबबंदी का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। बीजेपी ने कहा नारियों का सम्मान करेंगे, 12 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग करेंगे। इसलिए नारियों ने बीजेपी को बढ़-चढ़ कर वोट किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी ये बात तय हैं।

टीएस सिंहदेव बड़े लीडर हैं : दीपक बैज

रायपुर। टीएस बाबा के सीएम बनने के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। बैज ने कहा, वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत हैं। भाजपा को मुद्दा चाहिए, वो बड़े लीडर उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है।

कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा दो दिनों तक समीक्षा हुई, प्रत्याशियों से चर्चा हुई। पार्टी ने बेहतर चुनाव लडा है। 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 75 प्लस सीटों पर जीत कर आएंगे।

समीक्षा बैठक पर हुई शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कुछ शिकायतें आई। कुछ प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों ने शिकायत की है। शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। शिकायतों का परीक्षण कराएंगे कुछ गलत होगा तो कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार: रमन सिंह

रायपुर। 3 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने कहा, 3 दिसंबर को परिणाम का इंतजार सभी को है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और केंद्रीय नेतृत्व ने भी पर्याप्त समय दिया। पहले और दूसरे चरण के अभियान जिस तरह चले हैं, बीजेपी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हर क्षेत्र से सर्वे और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद निष्कर्ष यही निकला है। कम से कम 52 से 54 सीटों पर भाजपा जीत रही और भाजपा की सरकार बनेगी।

मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने और सीएम उम्मीदवारी पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वह सही बोल रहे हैं, उनके मन की पीड़ा है। पांच साल से वह इंतजार कर रहे हैं। यह वादा कर उनको पांच साल घुमा कर रख दिया गया, पर उनकी भी इच्छा गलत समय पर जागृत हुई है। अब बीजेपी की सरकार बन रही है।

कांग्रेस में अंतर्द्वंद्व पर रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस में अंतर्द्वंद्व पूरे चुनाव के दौरान दिखा। जितने बड़े नेता थे वह अपने विधानसभा छोड़कर कहीं नहीं गए। एक विधानसभा में बांधकर उन्हें रखा गया। अब उनके मन की पीड़ा और आक्रोश झलक रही है। दीपक बैज के महिलाओं को वोट देने के बयान पर रमन सिंह ने कहा, महिलाओं का रुझान बीजेपी की योजना और घोषणा पत्र पर है। कांग्रेस की वादाखिलाफी के आक्रोश को प्रकट किया है। महिलाओं को छला गया और ठगा गया। महिलाओं ने गुस्से में आकर शानदार मतदान किया है। यह परिवर्तन का वोट है, जो महिलाओं ने दिया।

ट्रेनों के रद्द होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, यह अस्थाई व्यवस्था है। जब ट्रैक पूरा होगा तो सबकी दिक्कतें दूर होगी। रेल मंडल से संपर्क में हैं। जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ की सुविधा बहाल होगी।

वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है

अवधेश कुमार

देश में इस समय एक साथ कई राज्यों में सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की स्थिति है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक छोटे से अंतराल में इतने राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच टकराव का मामला सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं पहुंचा था। इस वर्ष अभी तक तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पंजाब की सरकारें राज्यपालों के विरुद्ध कोर्ट जा चुकी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया तो केंद्र सरकार ने पहले अध्यादेश और बाद में संसद के जरिए कानून लाकर उसे पलट दिया। इन सबसे ऐसी धारणा बन रही है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों की तरह ही मौजूदा बीजेपी सरकार भी विरोधी पार्टियों वाली राज्य सरकारों के विरुद्ध राज्यपालों का दुरुपयोग कर रही है। कई ऐसी बातें हैं, जो इस परसेप्शन को मजबूती देती हुई लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में की गईं टिप्पणियां राज्यपालों के आचरण के विरुद्ध रही हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने के मामले में कोर्ट की टिप्पणियां काफी तीखी मानी गईं। दूसरी बात यह कि ये विधेयक काफी समय से राज्यपाल के पास पड़े थे। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने जिन 10 विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वापस किया, उनमें ज्यादातर पिछले वर्ष पारित हुए थे। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा रोके गए आठ विधेयकों में से तीन करीब दो वर्षों से और अन्य तीन 12 महीने से लंबित हैं। फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ अन्य तथ्यों पर गौर करने की जरूरत है। तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा रोके गए वि?धेयकों में से एक कुलपतियों की नियुक्ति मामले में राज्यपाल के अधिकार पर रोक लगाने वाला है। दूसरा एआईएडीएमके के चार पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति? मांगने से संबंधित है। तीसरा, 54 कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित है। केरल में रोके गए विधेयकों में से भी एक राज्यपाल को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने वाला है। जाहिर है, ये मामले राजनीतिक हैं और इन पर राज्यपालों के भी अपने तर्क रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का तर्क है कि राज्य सरकार कुलपतियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों को दे रही है लेकिन विश्वविद्यालयों को राज्य और केंद्र सरकार से धन मिलता है। व्यय के प्रावधान वाला हर विधेयक धन विधेयक होता है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता। लेकिन सरकार विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को धन विधेयक मान ही नहीं रही। पंजाब का मामला और भी विचित्र है। वहां राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा सत्र बुलाकर विधेयक पारित किया गया। राज्यपाल पुरोहित का कहना था कि चूंकि सत्र ही असंवैधानिक है, इसलिए इसमें पारित विधेयक भी असंवैधानिक हो गए। सरकार कह रही है कि बजट सत्र का अवसान नहीं हुआ था, इसलिए जून में नया सत्र था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा किया। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि इन राज्य सरकारों का व्यवहार संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। क्या यह सच नहीं है कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पदों पर ज्यादातर राज्य सरकारें योग्यता और क्षमता की अनदेखी कर मनमानी राजनीतिक नियुक्तियां करतीं हैं? क्या कुलपति होने के नाते राज्यपालों को अपनी सीमाओं में कदम उठाने या इन पर बोलने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं हो सकती, यह राज्यपाल और सरकार के बीच का विषय है। क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाकर कुछ विवादों का निपटारा नहीं कर सकते? केरल के राज्यपाल सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सामान्य जानकारी देने के अपने संवैधानिक कर्तव्य से भी भागते हैं, राजभवन नहीं आते।

इंडी एलायंस के लिए चुनाव

अजय सेतिया

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन तीन राज्यों में से दो राज्य इस समय कांग्रेस के पास हैं। महत्वपूर्ण तो भाजपा के लिए भी है। लेकिन भाजपा के लिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के पास अभी एक राज्य है मध्यप्रदेश। वह भी असल में वह पिछली बार हार गई थी। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा की झोली में डाल दिया था।

कांग्रेस तीनों में से दो राज्य हार गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। उसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। भाजपा तीन में से दो राज्य जीत जाए, तो उसके लिए उपलब्धि होगी। एक भी जीते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहां तक मोदी का सवाल है तो हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि तीनों राज्य हार कर भी लोकसभा चुनाव में मोदी ने इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ कर दिया था।

उससे पहले भी देख चुके हैं कि लोकसभा चुनावों पर राज्य विधानसभा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होता। लेकिन कांग्रेस अगर दो राज्य हार गई तो उसकी लोकसभा चुनावों की सारी रणनीति धरी रह जाएगी। खुद को दूसरों से बड़ा बताने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में इंडी एलायंस के किसी दल से गठबंधन नही किया। अलबत्ता तीन महीनों के लिए इंडी एलायंस को बर्फ में डाल दिया।

नीतीश, अखिलेश और केजरीवाल मध्यप्रदेश में सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने तीनों को ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस की रणनीति यह है कि वह पांच में से तीन राज्य जीत जाए। तेलंगाना और मिजोरम में तो वह सोच भी नहीं रही। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस को कड़ी टक्कर दे रही है। इसके बावजूद कांग्रेस तीनों हिन्दी भाषी राज्यों पर ही दांव लगा कर बैठी है।कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगर उसके मन मुताबिक़ नतीजे आए, तो वह क्षेत्रीय दलों को कहेगी कि वह अकेले भाजपा को हराने में सक्षम है। इसलिए सीटों के बंटवारे में उसका हक ज्यादा बनता है। लेकिन अगर कांग्रेस तीनों राज्यों या दो राज्यों में हार गई तो उत्तर भारत के सारे दल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को ठेंगा दिखाएंगे। न केजरीवाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भाव देंगे, न अखिलेश

यादव उत्तर प्रदेश में भाव देंगे। न लालू और नीतीश बिहार में उतना भाव देंगे, जितनी उम्मीद कांग्रेस लगा कर बैठी है। इसलिए तीनों राज्य जीतना कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीन महीने पहले तक कांग्रेस तीनों राज्यों में जीत रही थी। यह ओपिनियन पोल बता रहे थे। कांग्रेस ने इन्हीं ओपिनियन पोल को देख कर अखिलेश, केजरीवाल और नीतीश को भाव नहीं दिया। जबकि अब ओपिनियन पोल बदल चुके हैं। नए ओपिनियन पोल में भाजपा मध्यप्रदेश और राजस्थान जीत रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में महादेव एप ने मुकाबला कड़ा कर दिया।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री ने मतदान से एक दिन पहले ही राजस्थान में अपने चुनावी भाषण में इन दोनों राज्यों में जीत का दावा कर दिया। उन्होंने तो मुख्यमंत्री बघेल के हारने की भविष्यवाणी भी कर दी है। बघेल अपने चचेरे भाई विजय बघेल और अमित जोगी के साथ तिकोने मुकाबले में गए थे। अमित जोगी कांग्रेस के वोट काट कर विजय बघेल का रास्ता खोल रहे थे।

छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार में सरगुजा की बहुत भूमिका थी। यह टीएस सिंहदेव का इलाका है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी। इसलिए 2018 में सरगुजा की सभी 17 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। अब सरगुजा कांग्रेस के हाथ से खिसकता दिख रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने वायदा करके भी उन्हें ढाई साल बाद सीएम नहीं बनाया। मोदी ने चुनाव से दो दिन पहले यह कह कर आग में घी डाल दिया कि बघेल ने दस जनपथ में पैसे पहुंचा दिए थे। इसलिए टीएस सिंहदेव सीएम नहीं बन पाए। अब टीएस सिंहदेव खुद कह रहे हैं कि 17 में से सात-आठ सीटें जीत लेंगे। कुल मिलाकर इन सब बातों से जिस छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का सुरक्षित किला बताया जा रहा था। उस छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस को कड़ा मुकाबला दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी की एक एक राजनीतिक चाल महत्वपूर्ण होती है। वह आगे की सोच कर कदम रखते हैं। उन्हें पता था कि इन दोनों राज्यों में 14 नवंबर को प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 15 को भी प्रचार का मौक़ा ढूंढ लिया। चुनाव से 24 घंटे पहले उन्होंने झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर जाने का प्रोग्राम बना रखा था। वहां जाकर उन्होंने 24 हजार करोड़ की परियोजनाओं का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया था। भाजपा मानती है कि इससे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटरों पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा।

अब वोटिंग से अंदाज लगाना मुश्किल हो गया है। पहले माना जाता था कि अगर पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन मध्यप्रदेश में 2003 से ले कर इस बार तक वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। इसके बावजूद 2008 और 2013 में भाजपा जीती। 2018 में जब किसी को बहुमत नहीं मिला था, तब उसकी सीटें जरुर घटीं, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से आधा प्रतिशत ज्यादा था। इस बार भी 2018 के मुकाबले करीब आधा प्रतिशत वोट बढ़ा है। 2018 में 75.6 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 76.2 प्रतिशत वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 2018 में 76.45 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 75.72 प्रतिशत हुई है, यानि 0.73 प्रतिशत कम वोटिंग हुई।

मध्यप्रदेश जहां पिछली बार आधा प्रतिशत कम वोट के बावजूद भी भाजपा की सीटें कांग्रेस से पांच कम रह गई थी, वहां आधा प्रतिशत वोटिंग ज्यादा हुई है। छत्तीसगढ़ जहां पिछली बार भारी बहुमत से कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छिनी थी, जहां वोटिंग पौन प्रतिशत कम हुई है। ये आंकड़े और कुछ दिखाए या न दिखाएं, इतना संकेत जरुर देते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और मध्यप्रदेश में कांटे की टक्कर है।

राजस्थान में वोटिंग 25 नवंबर को है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में डेरा डाल लिया है। उधर मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व सरमा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की लंबी चौड़ी फ़ौज उतार दी है। मायावती भी बसपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंच चुकी है। मायावती अपने भाषणों में कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, भाजपा पर नही। संकेत साफ़ है कि वह भाजपा के प्रति सॉफ्ट है। राजस्थान में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तय है कि कांग्रेस ने दो राज्य नहीं जीते तो वह इंडी एलायंस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कान्फिडेंस लेवल ऊंचा है। वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले ही उन्होंने ट्विट करके मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत की गारंटी दे दी। जबकि राजस्थान में वहां के लोगों से जीत की गारंटी मांग रहे हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागकुण्डल्युपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

जहाँ गुल्फ (टखना) रखा जाता है, उसके समीपस्थ कन्द को दबाते हुए, पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए, इस प्रकार प्राण धीरे-धीरे पेट की सन्धियों में प्रवेश कर जाता है, इससे पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस क्रिया को निरन्तर करते रहना चाहिए।

पूरक के अन्त में वायु को रोकने के लिए कण्ठ संकोचन क्रिया करते हैं, जिसे जालन्धर बन्ध कहते हैं। मूलबन्ध के द्वारा अधोभाग में गुदा का संकोचन करके कण्ठ संकोचन अर्थात् जालन्धर बन्ध करे, बीच में (पेट में) उड्डियान बन्ध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। पूर्व में बतायी गयी विधि से ठीक तरह से आसन पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए। चारों प्रकार के कुम्भक को पहले दिन दस-दस बार किया जाता है, दूसरे दिन पन्द्रह - पन्द्रह बार कुम्भक करे। प्राणायाम के क्रम में तीसरे दिन बीस-बीस बार अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन पाँच-पाँच संख्या में बढ़ाता चले। कुम्भक का अभ्यास तीनों बन्धों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए।

दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अतिमैथुन, मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिन्तित रहना इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है।

मुझे योगाभ्यास के द्वारा रोग हो गया है, यदि कोई साधक यह कहकर अभ्यास बन्द कर दे, तो समझना चाहिए कि योगाभ्यास का यह पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न साधना पर शंका करना अर्थात् विश्वास न होना, तीसरा विघ्न प्रमत्तता है, चौथा विघ्न आलस्य करना, पाँचवाँ विघ्न ज्यादा नींद लेना, छठवाँ विघ्न साधना से प्रेम न होना, सातवाँ विघ्न भ्रान्ति, आठवाँ विघ्न विषय-वासना में अनुरक्ति, नवाँ अनाख्य (अप्रसिद्धि या अनाम) और योग तत्त्व का प्राप्त न होना दसवाँ विघ्न है, इस प्रकार ये दस विघ्न हैं, इन पर विचार करके बुद्धिमान् साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए।

इसलिए नियमित रूप से सत्त्वमयी बुद्धि से विचार कर प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार के चिन्तन से चित्त सुषुम्ना नाड़ी में लीन रहता है, जिसके कारण उसमें प्राणों का प्रवाह चलने लगता है।

क्रमशः ...

विश्व टेलीविजन दिवस

देवेन्द्रराज सुथार

मेरा टीवी है अनमोल, खोल रहा दुनिया की पोल। इसमें चैनल एक हजार, इसके बिन जीवन बेकार। सूचना क्रांति के इस युग में टेलीविजन मानवीय जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने में एक बड़ा माध्यम साबित हुआ है। आज पूरी दुनिया पर टेलीविजन का जादू छाया हुआ है। यह केवल मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन ही नहीं है बल्कि इसने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत संबंधों, यात्रा आदि के संदर्भ में भी ज्ञान का भंडार खोल दिया है। यह संस्कृतियों व रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान के रूप में उभरकर सामने आया है। आज टेलीविजन विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद कर रहा है।

वर्तमान में यह मीडिया की सबसे प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है। इससे विश्व संकीर्ण हुआ है और भूमंडलीकरण का असर दिखने लगा है। परिणामस्वरूप हम सुदूर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों का आनंद अब लाइव टीवी के जरिये घर बैठे लेने लगे हैं। बेशक टेलीविजन तकनीक का एक पहलू है। तकनीक अपने साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम लेकर आती है। टेलीविजन के कारण जहां ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन व शिक्षा-चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी जिज्ञासा शांत हुई है तो वहीं इसके माध्यम से हिंसा, अश्लीलता व भयभीत करने वाले कार्यक्रमों ने हमारी आस्था एवं नैतिक मूल्यों को चोट भी पहुंचाई है।

सच्चाई यह है कि वर्तमान में टेलीविजन से जुड़ा हर नया अनुभव हमारे जीवन को उत्तेजित कर रहा है।

गौरतलब है कि टेलीविजन की हमारे जीवन में बढ़ती भूमिका और इसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल, टेलीविजन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 17 दिसंबर, 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया। 1927 में फिलो टेलर फार्न्सवर्थ नामक 21 साल के लड़के ने आधुनिक टेलीविजन पर सिग्नल प्रसारित किया। 1926 से लेकर 1931 तक कई असफलताओं के बाद टेलीविजन में बदलाव होते रहे। 1934 आते-आते टेलीविजन पूरी तरह इलेक्ट्रानिक स्वरूप धारण कर चुका था। हालांकि, इससे पहले 1908 में ही मैकेनिकल टेलीविजन का आविष्कार हो चुका था। मैकेनिकल टीवी के बारे में बात करें तो यह रील वाली फिल्मों पर आधारित था। इसके प्रसारण के लिए बंद कमरा चाहिए होता था और प्रोजेक्टर और रील की मदद से वीडियो दिखाई जाती थी। लेकिन फिलो का टीवी आज के मॉर्डन टीवी की शुरूआत थी। वो बात अलग है कि उस वक्त कलर नहीं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ही टीवी पर दिखती थीं। 1927 में फिलो टेलर फार्न्सवर्थ द्वारा टीवी का आविष्कार किए जाने के 1 साल बाद अमेरिका में पहला टेलीविजन स्टेशन शुरू हुआ। सितंबर 1928 में जॉन बेयर्ड ने पहली बार मॉर्डन टीवी आम लोगों के सामने प्रदर्शित किया। जॉन बेयर्ड वही शख्स थे जिन्होंने मैकेनिकल टीवी का आविष्कार किया था। अगले 10 सालों तक टीवी मार्केट में नहीं आया। 1938 में औपचारिक तौर पर जॉन टेलीविजन को मार्केट में लेकर आए। अगले 2 सालों में आधुनिक टीवी के हिसाब से टीवी स्टेशन खुले और लोग बड़ी संख्या में टीवी खरीदने लगे। भारत में पहली बार लोगों को टीवी के दर्शन 1950 में हुए, जब चेन्नई के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक प्रदर्शनी में पहली बार टेलीविजन सबके सामने रखा। भारत में पहला टेलीविजन सेट कोलकाता के एक अमीर नियोगी परिवार ने खरीदा था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो ने रोजाना टीवी ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। 1976 में सरकार ने टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया। 1982 में पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल की शुरूआत हुई।

मालदीव में बदलाव और भारत

आनंद कुमार

हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के मोहम्मद सोलिह को हराने के बाद संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने अब मालदीव के नए राष्ट्रपति की भूमिका संभाल ली है। मालदीव में सत्ता परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश भू-राजनीतिक लिहाज से अहम बन गया है। माना जाता है कि नई सरकार ऐसी नीतियां अपनाएंगी, जो पिछली सरकार से बिल्कुल अलग होंगी। इसका क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत भारत ने मालदीव के नए राष्ट्रपति का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है। मोहम्मद मुइज्जू के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ गई है। जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, तब मुइज्जू उनकी सरकार में आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री थे। उस दौरान मालदीव पर चीन का व्यापक प्रभाव देखा गया था। तब चीन के हितों को देखते हुए फैसले लिए गए, जिससे विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू हुईं और मालदीव चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) में शामिल हो गया। बाद में आई सोलिह सरकार ने न सिर्फ चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से परहेज किया, बल्कि मालदीव में चीन के विवादास्पद संयुक्त महासागर निगरानी केंद्र की योजना से भी पल्ला झाड़ लिया।

यामीन का सबसे विवादास्पद निर्णय द्वीपों को विदेशी देशों को बेचना था। ऐसी आशंका थी कि चीन इन द्वीपों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। इससे मालदीव की संप्रभुता से समझौता होने की चिंता बढ़ गई। सौभाग्य से, यामीन अपने मंसूबों

में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। विडंबना देखिए कि जिस यामीन ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया, उसी ने उसकी रक्षा के नाम पर कथित तौर पर 'इंडिया आउट' अभियान चलाया। यामीन ने झूठा दावा किया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों ने वहां के लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाकर देश की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है।

यामीन के इंडिया आउट अभियान के समर्थक मुइज्जू ने इसका चुनावी लाभ उठाया, क्योंकि जेल में होने के कारण यामीन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। चीन से मुइज्जू की निकटता पिछले साल उनके दौरे से स्पष्ट हो गई थी, जब उन्होंने अपने गठबंधन के सत्ता में आने की स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की संभावना जताई थी। इसलिए हैरानी नहीं कि मुइज्जू के चुनाव जीतते ही चीनी राजदूत ने तुरंत उन्हें बधाई दी। यामीन और मुइज्जू की चीन के प्रति निकटता को देखते हुए हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव को कई लोगों ने भारत और चीन की भूमिकाओं पर जनमत संग्रह के रूप में देखा था।

चुनाव प्रचार के दौरान मुइज्जू ने मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत-मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत के पक्ष में है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कई बार दोहराया कि पद संभालने के पहले दिन से ही वह भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कदम उठाना चाहते हैं। कार्यभार संभालने से पहले ही उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के साथ इस पर चर्चा की और भारत से मालदीव के ऋण का पुनर्गठन करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस समय भारत मालदीव में करीब 45 बुनियादी परियोजनाओं में शामिल है, जिनमें से पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों की कुछ परियोजनाएं सीधे मालदीव के लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य पड़ोसी द्वीपों को राजधानी माले से जोड़ना है।

हालांकि मुइज्जू ने इस बात की पुष्टि की है कि वह पहले से चल रही भारतीय परियोजनाओं को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन अपने इस नजरिये में संभावित विरोधाभास दिखाते हुए उन्होंने समीक्षा का संकेत दिया है। यामीन के राष्ट्रपति काल में जीएमआर जैसी परियोजनाओं को 27 करोड़ डॉलर के मुआवजे के भुगतान के बाद भी अचानक रद्द कर दिया गया था। मुइज्जू ने अब तक केवल ऋण पुनर्भुगतान पर फिर से बातचीत की मांग की है, लेकिन भारतीय परियोजनाओं में कोई भी बाधा द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है।

एक दूसरी संभावित चिंता मुइज्जू का सलाफी विचारधारा से करीबी जुड़ाव है, जो द्विपक्षीय रिश्तों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। आईएस लड़ाकों में शामिल होने की बढ़ती संख्या के साथ मालदीव में मजहबी कट्टरवाद का उदय लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। वास्तव में सोलिह सरकार द्वारा कट्टरवाद के साथ सावधान रवैया ही एमडीपी में विभाजन का एक प्रमुख कारण था।

भारतीय सैनिकों की तैनाती को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले यामीन के साथ मुइज्जू का जुड़ाव वास्तव में भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और जटिल ही बनाने वाला है। मालदीव के विशाल समुद्री क्षेत्र को देखते हुए स्वतंत्र रूप से इसकी सुरक्षा मालदीव के लिए चुनौतीपूर्ण रही है और भारत को ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाले देश के रूप में देखा गया है। वर्ष 2004 की सुनामी और हालिया पेयजल संकट के दौरान सबसे पहले भारत ने ही मालदीव में मदद का हाथ बढ़ाया था। दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। मालदीव के लोग अक्सर चिकित्सा के लिए भारत आते हैं और भारतीय शिक्षक एवं डॉक्टर मालदीव के स्कूलों एवं अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं।

अतीत में मालदीव ने संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया, लेकिन यामीन की सरकार के दौरान यह अपनी राह से भटक गया। इससे चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाने में मदद मिली। अपने शपथ ग्रहण समारोह में मुइज्जू ने फिर दोहराया कि वह कूटनीतिक तरीकों से भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। कुछ लोग इसे मुइज्जू द्वारा मालदीव में भारत की स्थिति को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद हुसैन शरीफ ने पद संभालने के बाद पहली बार भारत आने की परंपरा का सम्मान करने और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में किसी बाहरी ताकत की भूमिका नहीं होने देने पर जोर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि कार्यभार संभालने के बाद मुइज्जू का रुख क्या रहने वाला है।

आज का इतिहास

1980 लास वेगास स्ट्रिप के एमजीएम ग्रांड होटल और कैसीनो में आग लगने से 85 लोग मारे गए।

1986 मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया।

1989 ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमंस में पहली बार कैमरे लगाए गए।

1996 लेबनान के राजनेता पियरे अमाइन गेमाएल , सीरिया की सैन्य उपस्थिति और लेबनान के राजनीतिक वर्चस्व की मुखर हत्या, जेडीह में हत्या कर दी गई थी।

1998 निन्दाडो ने द लीजेंड ऑफ ज़ेल्डा बुक रिलीज़ की= टाइम ऑफ़ ओरारिना

2002 बुल्गारिया,इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लेवानिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया।

2005 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्नसिरी विक्रमनायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

2006 एनास्टासियस द्वितीय की मृत्यु के बाद, सिम्माचस और लॉरेंटियस दोनों पोप चुने गए, जिससे एक ऐसा विद्वान पैदा हुआ जो 506 तक चलेगा।

2007 स्थानीय चुनावों के दौरान संघर्षों में छह लोगों के मारे जाने के बाद नाइजीरियाई सेना का आयोजन कानो राज्य में किया गया है।

2008 ऑटोमोबाइल की बिक्री कम होने के कारण, टोयोटा अपने जापानी अस्थायी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत से 6,000 से 3,000 तक की कटौती करता है।

2009 एक शोध के अनुसार, होमो फ्लोरेसेंसिस, एक विशिष्ट प्रजाति है जिसे वर्ष 2003 में खोजा गया था। यह बौनेपन या माइक्रोसेफली के साथ पहले से ज्ञात प्रजाति नहीं है।

2011 कंबोडिया के खमेर रूज शासन के तीन सबसे वरिष्ठ जीवित सदस्यों पर मानव जाति के खिलाफ नरसंहार और गलत काम करने के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है।

2012 इज़राइल और हमास के बीच एक विवाद, प्रभाव में आता है। यह मिस्र के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा घोषित किया गया था।

पुरानी पेंशन पर कितना असर करेगा गहलोत का दांव

जितेंद्र भारद्वाज

राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। राज्य में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सात चुनावी गारंटियों में पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी का दर्जा, इसे पहले नंबर पर रखा है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, अपनी रैलियों में %ओपीएस% के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही हैं। राजस्थान चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खासे आश्वस्त हैं। उन्होंने अब ओपीएस को कानूनी दर्जा दिए जाने का दांव चल दिया है। हालांकि उनके इस दांव में सियासी पेंच फंस सकता है। एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है। भले ही वह पैसा कर्मियों का है, लेकिन बिना केंद्र की सहमति के उसे राज्य सरकार को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की चुनावी गारंटी में शामिल, ओपीएस को अगर राज्य में कानूनी दर्जा मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किसी दूसरे दल की सरकार उस कानून को निरस्त नहीं करेगी। ऐसे में कानूनी दर्जे की खास अहमियत नहीं रह जाएगी।

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ ने सोमवार को बताया, देखिये ये एक भरोसे की बात है। राजस्थान सरकार, अपने कर्मियों को यह भरोसा दे रही है कि उन्होंने ओपीएस को महज एक चुनावी गारंटी तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपनी तरफ से उसे कानूनी दर्जा भी प्रदान कर दिया है। अब यह दर्जा तो एक प्रदेश में है। ऐसा संभव है कि किसी दूसरी पार्टी की सरकार, इस दर्जे को वापस भी ले सकती है। कानून में बदलाव कर सकती है। यहां पर देखने वाली बात ये है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने ओपीएस लागू किया है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी गारंटी में भी उसे कानूनी दर्जा देने की बात कही है। दूसरी तरफ भाजपा के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र तक नहीं है। ये बात भी ठीक है कि कर्मियों का एनपीएस में जमा पैसा, भारत सरकार के नियंत्रण में है। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी (पीएफआरडीए) में जमा पैसा, केंद्र की मर्जी के बिना राज्यों को नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार, इस बाबत पहले ही इनकार कर चुकी है।

बतौर तेज सिंह राठौड़, भारत सरकार को इस संबंध में सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब एनपीएस लागू किया तो उससे पहले कर्मियों से नहीं पूछा था। अब सरकार को चाहिए कि वह ओपीएस व एनपीएस का विकल्प, कर्मियों को दे। कर्मचारी खुद तय करें कि

उन्हें ओपीएस बहाली चाहिए या एनपीएस में रहना है। साथ ही पीएफआरडीए के नियमों में बदलाव किया जाए। राजस्थान में ओपीएस का असर, चुनाव में देखने को मिलेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। खासतौर पर, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में सरकारी कर्मियों का वोट, सत्ता समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी, अगर पूरी तरह से ओपीएस के समर्थन में मतदान करते हैं, तो चुनावी नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। राजस्थान में नौ से दस लाख सर्विंग/रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनके परिवार भी हैं। यह संख्या, विधानसभा चुनाव में सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है।

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, तो वेट नहीं, वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लॉक कीजिए। केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठनों के नेता भी कह चुके हैं कि ओपीएस का विरोध कर भाजपा, सियासत में एक बड़ा जोखिम ले रही है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकारें, बिना केंद्र के सहयोग से लंबे समय तक आगे नहीं चल सकती हैं। एनपीएस का पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीएफआरडीए) में जमा है। यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। केंद्र की मर्जी के बिना, एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार, इस बाबत साफ इनकार कर चुकी है।

पुरानी पेंशन बहाली के लिए तीन नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मियों ने चेतावनी रैली आयोजित की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के बैनर तले आयोजित हुई इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन सहित करीब 50 कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। कर्मियों का कहना था कि केंद्र सरकार को ओपीएस सहित दूसरी मांगों पर सकारात्मक विचार करना होगा। अगर केंद्र सरकार, एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली जैसी अन्य मागें नहीं मानती हैं, तो कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा कठोर कदम भी उठा सकते हैं। कर्मियों की मुख्य मांगों में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल था। कर्मियों का कहना था कि सरकार, पीएफआरडीए को वापस ले। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक विभिन्न राज्यों में लागू हो रही ओपीएस की राह मुश्किल ही बनी रहेगी। वजह, एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है, वह पीएफआरडीए के पास जमा है। केंद्र सरकार, कह चुकी है कि वह पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे में जहां भी ओपीएस लागू हो रहा है, वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू किया जा सकता है। ऐसे में राज्यों द्वारा की जा रही ओपीएस बहाली में कई पेंच फंसे रहेंगे।

जो राज्य, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का एलान कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वजह, केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। संभव है कि जो प्रदेश, ओपीएस लागू कर रहे हैं, उनके लिए केंद्र से अतिरिक्त कर्ज मिलने की राह मुश्किल हो जाएगी। एनपीएस के तहत राज्य सरकारें, अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी को देती हैं। इसे बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें, केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं। यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी तक हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकारों और केंद्र के बीच ठन गई है। जिन गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है, उन्हें %एनपीएस% में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया है कि यह पैसा %पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी% (पीएफआरडीए) के पास जमा है। नई पेंशन योजना %एनपीएस% के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा, जो इसका योगदान कर रहे हैं।

तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के लिए बीआरएस कांग्रेस-एआईएमआईएम में रस्साकशी

जलज मिश्रा

तेलंगाना की राजधानी में खाने में हैदराबादी बिरयानी और राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के जिक्र से बातें शुरू होती हैं। वैसे ओवैसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। इसलिए प्रमुख लड़ाई सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस में ही है। हालांकि भाजपा को भी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे से उम्मीद है। पीएम मोदी सिकंदराबाद में जोरदार रैली कर भी चुके हैं। ओवैसी का तिलिस्म तोड़ने की जद्दोजहद में कांग्रेस बीआरएस के साथ ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के खिलाफ सियासी तीर चला रही है। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को चुनाव होंगे। दूसरे राज्यों में चल रहे चुनाव के बाद यहां सभी पार्टियों के दिग्गज लगातार मैदान में उतरेंगे। एयरपोर्ट से कैब में बैठते ही ड्राइवर से चुनावी चर्चा करने की कोशिश की। मुझे थोड़ा-थोड़ा हिंदी आता है पर आप पूछिए मैं सब बता देगा, यह कहते हुए वैंकटेश ने टूटी-फूटी हिंदी में कहा, इस बार कांग्रेस के चांस ज्यादा लग रहे हैं। बीआरएस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, योजनाओं का सही फायदा गरीब को नहीं हुआ। भाजपा के सवाल पर वैंकटेश का जवाब था-प्रदेश अध्यक्ष बदलने का भाजपा को नुकसान हुआ है। ओवैसी पर जवाब मिला कि उनकी अपने लोगों में काफी पकड़ है। 119 विधानसभा सीटों में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महज नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद जिले में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव की राजनीति उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है। विरोधियों का सवाल है कि बिहार-यूपी में विधानसभा चुनावों ही नहीं नगर पालिका तक में लड़ाने वाले औवैसी अपने राज्य में पीछे क्यों हट रहे हैं। पिछले दो चुनावों में ओवैसी का रुझान बीआरएस की ओर है। इसका लाभ भी मिला और दो बार से प्रदेश में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार है। इस बार भी ओवैसी की पार्टी का रुख बीआरएस की ओर हैं। एक पोस्टर में ओवैसी के पीछे भाजपा होने की बात है। पोस्टर में मेरठ के मेयर चुनाव में ओवैसी के प्रत्याशी व सपा के वोट भाजपा के सामने दिखाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न चुनावों में बिहार और यूपी की तीन अन्य सीटों का जिक्र है। सभी में दिखाया गया है कि ओवैसी ने प्रत्याशी न उतारे होते तो भाजपा नहीं जीतती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के ओवैसी को संघ से जुड़ा बताने वाले बयान ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। पलटवार करते हुए ओवैसी ने रेवंत को आरएसएस का आदमी बता दिया। साथ ही कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस की कठपुतली हैं। बीआरएस रेवंत-ओवैसी झड़प को अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है। यही वजह है कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामाराव भी रेवंत को संघ की पृष्ठभूमि का बताकर हमला करते हैं। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ओवैसी और बीआरएस मिले हुए हैं। दरअसल बीआरएस को भाजपा के साथ दिखाने में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की कवायद है। ओवैसी इसीलिए इस चुनाव में और ज्यादा अहम हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक ननचैरय्या मेरूगमला का कहना है, सारा खेल मुस्लिम वोटों के इर्दगिर्द है। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 12 से 14 प्रतिशत के बीच है। 20 सीटों पर प्रभावी संख्या है और 20 अन्य पर किसी भी दल को जिता या हरा सकते हैं। इसी से ओवैसी अहम बने हुए हैं। कांग्रेस के साथ ओवैसी का अलगाव किरण रेड्डी के मुख्यमंत्री काल में बढ़ गया। तब से ओवैसी का झुकाव बीआरएस की ओर ही है। साथ ही कहते हैं, यह चुनाव भी पिछली बार की तरह एकतरफा ही जा सकता है। पिछली बार 119 में बीआरएस को 88 सीटें मिली थीं। मेरूगमला कहते हैं कि इसी को बदलने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम के मुताबिक, तेलंगाना में इस बार भाजपा बदलाव लाएगी।

डरावनी हैं चुनावों के दौरान मुफ्त वस्तुएं देने की घोषणाएं

अवधेश कुमार

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को वस्तुएं मुफ्त प्रदान करने की प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से प्रबल होती दिखी है। अंग्रेजी में इसके लिए फ्रीबीज शब्द प्रयोग किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों की इस प्रवृत्ति पर गहरी चिंता प्रकट की। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों में इसे देश के लिए चिंताजनक बताया। उन्होंने जनता को आगाह किया था कि ऐसे लोग आपको कुछ भी मुफ्त देने का वादा कर सकते हैं लेकिन इसका असर देश के विकास पर पड़ेगा बावजूद आप देखेंगे कि हर पार्टी अपने संकल्प पत्र, गारंटी पत्र या घोषणा पत्र में मुफ्त वस्तुएं, सेवाएं या नगदी वादों की संख्या बढ़ा रही थी। वैसे तो इसकी शुरुआत 80 और 90 के दशक में दक्षिण से हुई लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसे दोबारा वापस लाया। दिल्ली की जनता से बहुत कुछ मुफ्त देने के वायदे किए और उनको चुनाव में विजय मिल गई। कांग्रेस और भाजपा ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई तथा अपनी घोषणाओं में परिपक्वता का परिचय दिया। यह प्रवृत्ति बाद में कायम नहीं रह सकी। पांच राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में दलों के घोषणा पत्रों में मुफ्त सेवाओं, वस्तुओं और नगदी के वायदों के विवरणों को लिखने के लिए पूरी पुस्तिका तैयार हो गई। इसे आप मतदाता को घूस देना कहिए, लोकतंत्र का अपमान या और कुछ, यह स्थिति डराने वाली है। हमारे देश के ज्यादातर राज्य वित्तीय दृष्टि से काफी कमजोर पायदानों पर खड़े हैं और लगातार कर्ज लेकर अपने खर्च की पूर्ति कर रहे हैं यानी अनेक राज्यों की राजस्व आय इतनी नहीं है कि वह अपने वर्तमान व्यय को पूरा कर सकें। कई राज्यों के व्यय के विवरण का विश्लेषण बताता है कि मुफ्त चुनावी वादों को पूरा करने या भविष्य के चुनाव को जीतने की दृष्टि से मुफ्त प्रदानगी वाले कदमों की इसमें बड़ी भूमिका है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में समय पर कर्मचारियों का वेतन देने तक की समस्या खड़ी हो गई थी। दिल्ली ऐसा अकेला राज्य नहीं था। जब राज्य अकारण नगदी देने लगें तो फिर लोगों में परिश्रम से जीवन जीने और प्रगति करने का भाव कमजोर होता है। कोई भी देश तभी ऊंचाइयां छू सकता है जब वहां के लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करें। विश्व में जिन देशों को हम शीर्ष पर देखते हैं वहां के लोगों ने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम से इसे प्राप्त किया है। अगर राजनीतिक दलों में मुफ्त देने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए तो उस देश और समाज का क्या होगा, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है।

राजस्थान चुनाव को भाजपा ने दे दिया है दिलचस्प मोड़

नीरज कुमार दुबे

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कुछ लोक लुभावन योजनाएं शुरू कीं और इनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेता अपनी सभाओं में जनता से कहने लगे कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो वह इन योजनाओं को वापस ले लेगी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जायेगा बल्कि उसमें और सुधार कर उसे और जनउपयोगी बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरते हुए यह ऐलान भी कर दिया है कि 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा की जायेगी।

देखा जाये तो केंद्र सरकार ने जब उत्पाद शुल्क में कटौती की थी तो अन्य कई राज्यों ने भी वैट की दरें घटा दी थीं जिससे जनता को महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत मिली लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया और यहां के लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 12 से 13 रुपए ज्यादा देते हैं। देखा जाये तो यह अंतर बहुत ज्यादा है और इससे कांग्रेस के महंगाई से राहत देने के वादे और दावे पर भी सवाल उठता है।

राजस्थान की आबादी चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, इसीलिए भाजपा ने जनता को यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालना राज्य में मुश्किल हो गया है, भाजपा ने यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा लोगों को यह भी याद दिला रही है कि कैसे 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया गया था।

देखा जाये तो चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में स्थानीय मुद्दे दरकिनार होते जा रहे हैं। आइये आपको सिर्फ आज ही के

दिन भाजपा नेताओं की जनसभाओं और संवाददाता सम्मेलन के कुछ अंश बताते हैं जिससे आपके समक्ष स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्थान का चुनाव किस ओर बढ़ चला है। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी (घमंडिया गठबंधन) सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ये करने देंगे? प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार की लूट का एक उदाहरण यहां पेट्रोल की कीमतें हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार इन राज्यों से प्रति लीटर 12-13 रुपये महंगा पेट्रोल बेचती है। उन्होंने कहा कि मैं आज राजस्थान को गारंटी देता हूं कि 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार बनने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है और वह दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। मोदी पाली में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''आज पूरा देश विकसित होने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो उसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।'' उन्होंने कहा ''%दुर्भाग्य से यहां पिछले पांच साल से जो कांग्रेस सरकार रही है, उसने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए परिवारवाद ही सबकुछ है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में पांच वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर एक बना दिया है।'' मोदी ने यह भी आरोप लगाया ''कांग्रेस व इसके %घमंडिया% साथियों की सोच महिला विरोधी है।'' मोदी ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों से मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, वहां एक स्वर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है- जन जन की है यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार।%%

वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान राम नवमी की यात्रा को रोका गया, कांवड़ यात्रा को रोका गया, 300 साल पुराना मंदिर ढहा दिया, 18 से अधिक संतों की हत्या हुई, मंदिरों का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि अब 25 नवंबर को आप इनकी सरकार ढहा देना। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने सनातन संस्कृति पर हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है तबसे कांग्रेस में फैंसी ड्रेस कम्पीटिशन चल पड़ा है। कोई यज्ञ कर रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है।

केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी और बढ़ी तो यूपी में बढ़ सकती हैं भाजपा की मुश्किलें

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मौर्या बीजेपी का बड़ा चेहरा है। खासकर पिछड़ा समाज को लुभाने के लिए बीजेपी आलाकमान वर्षों से केशव प्रसाद मौर्या की 'ताकत' का इस्तेमाल करता रहा है। पूर्वांचल में केशव का खास दबदबा है। केशव की ताकत का अंदाजा इसी से लग जाता है कि बीजेपी ने 2017 के विधान सभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्या को एक तरह से सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को बड़े अतंर से हरा का सामना पड़ा था, लेकिन जब सीएम बनने की बारी आई तो केशव मौर्या को उनके खिलाफ चल रहे कुछ मुकदमों का हवाला देते हुए साइड लाइन कर दिया गया और बीजेपी आलाकमान ने हिन्दुत्व का नया प्रयोग करते हुए सीएम के रूप में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे कर दिया। परंतु बाद में पिछड़ों की नाराजगी को भांपते हुए केशव प्रसाद मौर्या को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई, जिस पर बैठने से पहले तो केशव ने मना कर दिया, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्हें बेमन से डिप्टी सीएम बनना पड़ गया। उनके साथ ही ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डा0 दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। बाद में दिनेश शर्मा की जगह बृजेश पाठक को यह (उप मुख्यमंत्री की) जिम्मेदारी सौंप दी गई।

केशव डिप्टी सीएम तो बन गये थे, लेकिन इसके साथ ही उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठने की खबरें भी आने लगीं। केशव प्रसाद मौर्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कालीदास मार्ग पर सरकारी आवास अगल-बगल था, परंतु दोनों के बीच मुलाकात नहीं होती थी। हद तो तब हो गई जब केशव प्रसाद मौर्या के पिता जी का निधन हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके आवास जाकर शोक व्यक्त करने में हफ्ते भर का समय लग गया। इसके बाद तो अक्सर ही कुछ महीनों के अंतराल पर योगी और केशव के बीच मनमुटाव की खबरें आम होने लगीं, जिसको समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खूब हवा देते हैं। अखिलेश डिप्टी सीएम को स्टूल वाला उप मुख्यमंत्री तक कह कर संबोधित करते रहे हैं। वह अक्सर कहते रहते हैं कि केशव यदि समाजवादी पार्टी में आ जायें तो समाजवादी पार्टी उन्हें सीएम बना देगी।

दरअसल बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्या की बेइज्जती की खबरें फैला कर अखिलेश पिछड़ों को बीजेपी की खिलाफ भड़काने की मुहिम लम्बे समय से चला रहे हैं। इधर आजकल एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्या की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। हाल ही में अयोध्या में योगी की कैबिनेट की बैठक और इसके बाद अयोध्या में ही दीपोत्सव कार्यक्रम से लेकर अन्य कई सरकारी कार्यक्रमों में केशव प्रसाद मौर्या की अनुपस्थिति को केशव की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं क्या ये महज एक संयोग है या फिर बात कुछ और है। आजकल केशव प्रसाद मौर्य के मन में क्या चल रहा है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बात जुबान से कही जाए। कई

बार तो इशारे और कुछ मौकों पर उनकी गैर मौजूदगी ही सब कुछ कह जाती है। जिन्हें समझना है वे समझ ही जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्या पिछड़ा समाज से आते हैं और पिछड़ा समाज को लुभाने के लिए बीजेपी एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, फिर केशव की अनदेखी क्यों हो रही है, इस सवाल का जवाब हर जागरूक नागरिक और बीजेपी के नेता/कार्यकर्ता जानना चाहते हैं। केशव की नाराजगी या कहें कि पार्टी में उनकी अनदेखी के चलते राजनीति के गलियारे में यह चर्चा आम है कि बीजेपी क्यों किसी बड़े दलित या पिछड़ा समाज के नेता को आगे बढ़ा या पचा नहीं पाती है। आज बीजेपी में पिछड़े और दलित नेताओं का पूरी तरह से अभाव है, जो एक-दो दलित या ओबीसी नेता सामने दिखाई भी देते हैं, उनकी अपने समाज में पैठ नहीं के बराबर है। कुल मिलाकर आज की तारीख में बीजेपी आलाकमान ने दलितों और ओबीसी को लुभाने के लिए अपने कुछ अगड़ी जाति के नेताओं को आगे कर रखा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समय यह सही तरह से पता चल पायेगा कि दलितों और ओबीसी समाज को ऊंची जाति के रहनुमाओं की सरपरस्ती कितनी रास आती है।

सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव के मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। इसीलिये पूछा जा रहा है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या क्यों नहीं गए? जितने लोग, उतनी बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री उस दिन वहां मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य के लिए हेलिकॉप्टर लखनऊ में था। अयोध्या रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम पाठक अपने सहयोगी डिप्टी सीएम मौर्य के घर पहुंचे। दोनों को एक ही हेलिकॉप्टर से अयोध्या जाना था। लेकिन केशव मौर्य ने पेट में दर्द के कारण अयोध्या यात्रा रद्द कर दी। ब्रजेश पाठक को अकेले अयोध्या जाना पड़ा। बताया जाता है कि इसी हेलिकॉप्टर में एक ऐसे व्यक्ति बैठे थे जिनका साथ डिप्टी सीएम केशव को पसंद नहीं है। पर क्या यही असली वजह थी, यह केशव ही बता सकते हैं। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों में केशव प्रसाद कई मौकों पर गैर हाजिर रहे। लखनऊ से बाहर पहली बार अयोध्या में 9 नवंबर को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी सरकार के सभी मंत्रियों ने पहले हनुमान गढ़ी में पूजा की। फिर सबने रामलला के दर्शन किए। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव नहीं पहुंचे। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक में केशव के न पहुंचने पर बताया गया उन्हें एमपी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी इसलिए वह नहीं आ पाये। इसके बाद लखनऊ में होते हुए भी जब मौर्य अयोध्या में हुए भव्य दीपोत्सव में नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। गौर करने की बात यह है कि इससे पूर्व लखनऊ में होने पर भी मौर्य 31 अक्टूबर की कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। उसी दिन मुख्यमंत्री ने लोकभवन में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखी, लेकिन उसमें भी मौर्य दिखाई नहीं दिए। उस दिन लखनऊ में आयोजित दूसरे कार्यक्रमों में भी मौर्य शामिल नहीं हुए थे। खैर, बात जहां तक केशव की नाराजगी में विपक्ष के चटखारे लेने की है तो समाजवादी पार्टी तो केशव के मामले में मौके की ताक में बैठी ही रहती थी। उसे ये मौका सोशल मीडिया के एक पोस्ट से मिल गया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक री पोस्ट किया था। बाद में उसे हटा लिया गया। डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां अपना वेतन बढ़ाने को लेकर धरने पर थीं। इस पर एक रिपोर्ट को डिप्टी सीएम केशव ने री पोस्ट कर दिया था। समाजवादी पार्टी के चर्चित प्रवक्ता आईपी सिंह ने उनका ये पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी पिछड़ा और दलित विरोधी है। जातीय जनगणना की मांग करने के कारण बीजेपी अब डिप्टी सीएम मौर्य से किनारा कर रही है। पिछले दो कैबिनेट की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए हैं। बात 31 अक्टूबर की है। लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग थी। उसी दिन सवेरे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में वे योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। पर कुछ ही घंटे बाद हुई कैबिनेट बैठक में उनका इंतजार ही होता रहा। उसी दिन कंगना रनौत की फिल्म तेजस का प्रीमियर शो भी रखा गया था। इसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री आए, पर डिप्टी सीएम मौर्य नहीं देखे गए।

वकालत में कैरियर

गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में लॉ ग्रेजुएट्स की डिमांड बढ़ रही है। कॉरपोरेट सेक्टर में तो बकायदा लीगल एडवाइजर अपाइंट किए जा रहे हैं। मीडिया में भी लॉ रिपोर्टिंग के लिए आज लॉ ग्रेजुएशन के बाद करियर के कई नए ऑप्शंस सामने आए हैं। पारंपरिक तौर पर कोर्ट और वकालत का क्षेत्र तो है ही, इसके अलावा तमाम कंपनियां अपने यहां लीगल ऑफिसेज भी खोलती हैं। इसमें टैक्सेशन, सेल टैक्स, आदि मामलों को देखने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को रखा जाता है।

अगर स्टूडेंट्स किसी दूसरे देश के लॉ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करता है, तो उसे एब्रॉड में भी मौका मिलता है। इन सबके अलावा एक बडा काम लीगल राइटिंग का भी है। यही कारण है कि लॉ में करियर की राह आज ज्यूडिशियरी तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि प्रशासन से लेकर मैनेजमेंट तक फैल गई है। इंडस्ट्री में लॉ प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से अब क्लैट के माध्यम से सीनियर सेकंडरी के बाद ही एंट्री शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में करियर के अनेक ऑप्शन होने के कारण यूथ के बीच लॉ ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगर आपको भी यह फील्ड लुभा रहा है, तो किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री लेकर लॉ में करियर बना सकते हैं।

कैसे लें एंट्री

लॉ में दाखिले के लिए अब अलग-अलग टेस्ट देने की बजाय कैट, मैट की तर्ज पर क्लैट शुरू किया गया है। कॉमन ला एडमिशन टेस्ट, यानी एक ही प्रवेश परीक्षा के जरिए लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज में पढने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा बहुत से कॉलेज अपने यहां अलग एंट्रेंस एग्जाम के जरिए भी एलएलबी में एडमिशन दे रहे हैं। 5 ईयर्स एलएलबी में 12वीं पास स्टूडेंट्स को आ?र्ट्स, कॉमर्स या साइंस में 50 परसेंट होने चाहिए। इसके बाद दो वर्षीय एलएलएम में एडमिशन के लिए एलएलबी में 55 परसेंट मा?र्क्स जरूरी हैं। बेहतर होगा कि आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उस कॉलेज के बारे में पहले जानकारी ले लें।

क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस

अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लॉ के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही बेहतर है। विशेषज्ञों के अनुसार देश में बहुत सारे प्राइवेट लॉ कॉलेजेज हैं, जहां क्वॉलिटी एजुकेशन के साथ ही कैंपस प्लेसमेंट होता है। इसलिए स्टूडेंट्स उन्हीं कॉलेजों या इंस्टीट्यूट को प्रिफरेंस दें, जहां फैकल्टी मेंबर्स योग्य और अनुभवी हों, कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा हो और इसके साथ ही क्वॉलिटी एजुकेशन पर फोकस हो। इस तरह की सुविधा इन दिनों अच्छी प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप क्वॉलिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ रख कर सकते हैं।

स्कोप

लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, साथ ही स्टेट लेवल पर ज्यूडिशियरी में भर्ती के लिए समय-समय पर एग्जाम्स भी आयोजित किए जाते हैं। यहां प्रॉसिक्यूटर, जिसे सरकारी वकील कहा जाता है, के रूप में काम करने का मौका है। ज्यूडिशियरी सर्विसेज में एग्जाम के जरिए राज्यों में जूनियर स्तर पर जज की भर्ती होती है।

बाजारीकरण और उदारीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद देश भर में बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज का एक्सपैंशन हुआ है। देशी-विदेशी कंपनियां शहर से लेकर गांव तक बिजनेस को बढावा दे रही हैं। इनके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर भी अपने पैर पसार रहा है। ऐसी व्यवस्था में कॉमर्स और मैनेजमेंट के अलावा लार्ज स्केल पर लॉ ग्रेजुएट्स को भी जॉब्स मुहैया कराई जा रही हैं। कंपनियों और लीगल फर्म में बतौर ऑफिसर या एडवाइजर के रूप में लॉ स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है।

प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक सिर्फ मैनेजर, अकाउंटेंट या क्लर्क ही नहीं, अपने यहां लॉ ऑफिसर भी नियुक्त कर रहे हैं। इसी तरह टैक्सेशन से जुडी कंपनियां अपने यहां लॉ के विशेषज्ञों को रख रही है। एमएनसी में मैनेजमेंट की टीम में एक लॉ एक्सपर्ट को भी मैनेजर के रूप में रखा जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों और बैंकों के एक्सपैंशन ने लॉ ग्रेजुएट्स को जॉब के नए ऑप्शन दिए हैं। मीडिया वर्ल्ड में भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रास्ते खुल रहे हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की लॉ रिपोर्टिंग के लिए न्यूज इंडस्ट्री लॉ प्रोफेशनल्स को प्रिफरेंस दे रही हैं। इसके अलावा टीचिंग के लिए आमतौर पर एलएलएम व नेट या पीएचडी छात्रों को करियर मुहैया कराया जा रहा है। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है।

करियर स्कोप

- कॉर्पोरेट लॉयर
- लीगल एडवाइजर
- साइबर लॉ एक्सपर्ट
- टीचिंग
- लीगल रिपोर्टिंग
- बैंक में लॉ आफिसर
- प्रॉसिक्यूटर
- जज

टॉप 10 डिमांडिंग जॉब्स में शामिल हुआ डिजिटल मार्केटिंग

जानें कैसे बनेगा इसमें आपका कॅरिअर

भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। सीआईआईई के एक हालिया सर्वे के अनुसार देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है। शहरी इलाकों में हालांकि बेरोजगारी दर बढ़ने का प्रतिशत काफी कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये 10त्न से ऊपर निकल गई है। जबकि बीते वर्ष इसी दरम्यान इसका प्रतिशत 7% के आसपास था। देश विदेश के बाजार में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम ने अब देश के युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग में दक्ष बनाने के लिए एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप इस लिंक Advanced Digital Marketing Programme पर क्लिक करके इस खास कोर्स से जुड़ सकते हैं और घर बैठे इस कोर्स को पूरा करके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना कॅरिअर बना सकते हैं।

मास्टर डिजिटल मार्केटिंग

प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग- टॉप 10 डिमांड्स वाली जॉब में शामिल हुआ डिजिटल मार्केटिंग

लोगों को नौकरी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली वेबसाइट लिंक्डइन के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर नौकरियां देने में मौजूदा समय में टॉप 10 क्षेत्रों में शुमार है। क्योंकि हर साल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की डिमांड हर साल 30 फीसद दर के हिसाब से बढ़ रही है। यानी आने वाले कई सालों तक इस फील्ड में नौकरियों की कोई कमी नहीं होने जा रही है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है और यह आपकी बेरोजगारी की समस्या को भी दूर कर सकता है।

डिजिटल सेक्टर की टॉप नौकरियां

मार्केटिंग मैनेजर- मार्केटिंग मैनेजर एक व्यवसाय के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीति तैयार करते हैं और उसका क्रियान्वयन कराते हैं। टीम लीड करते हुए वह विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का काम करते हैं। **सालाना पैकेज - 8 से 10 लाख रुपये**

सोशल मीडिया मार्केटर- सोशल मीडिया मार्केटर व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके लक्षित दर्शकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए काम करते हैं। उनके निर्देशन में ही सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री तैयार की जाती है। वो सोशल मीडिया अभियानों का प्रबंधन करने के साथ साथ सोशल मीडिया चैनल के परफॉर्मेंस का विश्लेषण भी करते हैं। सालाना पैकेज - 4 से 6 लाख रुपये

कॉपीराइटर- कॉपीराइटर व्यवसायों के लिए विज्ञापन, वेबसाइट सामग्री, और अन्य मार्केटिंग सामग्री लिखने का काम करते हैं। उन्हें टार्गेट ऑडियंस के हिसाब से रचनात्मक सामग्री लिखनी होती है। साथ ही वह प्रभावी कंटेंट तैयार करने में माहिर होते हैं। **सालाना पैकेज - 3 से 5 लाख रुपये**

ग्राफिक डिजाइनर- ग्राफिक डिजाइनर व्यवसायों के लिए विज्ञापन, वेबसाइट सामग्री, और अन्य मार्केटिंग सामग्री डिजाइन करते हैं। ग्राफिक डिजाइनरों को रंग सिद्धांत, टाइपोग्राफी आदि की बेहतर समझ होती है। **सालाना पैकेज - 5 से 6 लाख रुपये**

एसईओ विशेषज्ञ- एसईओ विशेषज्ञ कंपनी की वेबसाइट के सर्च इंजन परिणाम पृष्ठों को उच्च रैंक पर लाने का काम करते हैं। ये एसईओ की टेक्नोलॉजी से परिपक्व होते हैं। जिसके जरिये ये वेबसाइट कंटेंट को किसी भी सर्च इंजन पर अधिक खोजे जाने योग्य बनाते हैं। **सालाना पैकेज - 5 से 7 लाख रुपये**

एसईएम विशेषज्ञ- एसईएम विशेषज्ञ कंपनियों के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग अभियानों को चलाने का काम करते हैं। जिससे कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए लक्षित दर्शकों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम हो पाती है। **सालाना पैकेज 4 से 6 लाख रुपये**

ईमेल मार्केटर- ईमेल मार्केटर व्यवसायों के लिए ईमेल अभियानों का निर्माण और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे अक्सर लक्षित दर्शकों को आकर्षित करने और उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावी ईमेल सामग्री लिखने में माहिर होते हैं। **सालाना पैकेज - 5 से 6 लाख रुपये**

कैरियर में सफलता के लिए...

हर कोई अपने जीवन व करियर को सफल और संतुष्टिजनक बनाना चाहता है। करियर में सही मुकाम हासिल करने की राह में लोग कई तरह के प्रयोग करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में उनसे कई तरह की गलतियां भी होती हैं। हम आपको यहां कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने करियर को सफल और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं और आपके लिए शिखर पर पहुंचने की राह आसान हो सकती है।

काम का कोई उद्देश्य हो

आपकी मौजूदा भूमिका जो भी हो, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। सफलता की कुंजी यह है कि आज पर फोकस रखते हुए भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। आपको अपनी करियर आकांक्षाओं और मौजूदा जॉब के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। समूची प्रकिया को एंज्वॉय करिए, क्योंकि इसी तरह से सीखा और आगे बढ़ा जा सकता है।

लीडरशिप जरूरी है

किसी सफल करियर को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है, कुशल नेतृत्व का गुण सीखना। ध्यान रहे, यदि आप बहुत गहरी खाई में उतर कर नेतृत्व करने लगते हैं तो आपको ऐसी किसी सुविधाजनक जगह पहुंचने में मुश्किल आएगी जहां से रणनीतिक नेतृत्व कर सकते हों। इसी तरह, बहुत ऊंचाई पर चढ़कर नेतृत्व करने से आप अपनी टीम से कट जाएंगे, अलग-थलग पड़ जाएंगे और आपको सिर्फ अपने लिए नेतृत्व करने वाला समझा जाएगा। एक सफल नेतृत्व और सफर करियर के लिए यह जरूरी है कि आपको अपने कर्मचारियों के बीच समुचित सम्मान मिले। इसके लिए आपको टीम को साथ लेकर चलना सीखना होगा।

एकला न चलें

ध्यान रहे कि करियर का निर्माण कभी भी अकेले दम पर नहीं हो सकता। आप किसी महान शेफ के साथ किचन में जाएं तो देखेंगे कि उसके साथ कई शेफ की पूरी टीम लगी हुई है और इस टीम के पूरे लय में मिलकर काम करने के बाद ही कोई स्वादिष्ट डिश तैयार होती है। इसी तरह बिजनेस या नौकरी में भी सफलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। आपको अपने प्लान को लागू कराने के लिए सक्षम सहकर्मियों, मित्रों आदि की जरूरत होती है। इसके अलावा, आपको समय-समय पर भरोसेमंद लोगों की सलाह की जरूरत भी पड़ती है।

ऊपर ही नहीं, अगल-बगल भी देखें

अक्सर लोग सफलता की ओर बढ़ने का एकमात्र तरीका यह मान लेते हैं कि सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ते चला जाए। लेकिन कई बार यह तरीका सही नहीं होता। जब आप सीढ़ी पर वर्टिकल चढ़ते जाते हैं तो अपनी टीम से कट जाते हैं और कई हॉरिजंटल मौकों को गंवा देते हैं। अपने अगल-बगल देखते हुए भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इस तरह मिलने वाले अवसरों का फायदा उठाएं, अन्यथा यह भी हो सकता है कि जल्दबाजी में आप सीढ़ियां चढ़ते जाएं और टॉप पर पहुंचने के बाद ऐसा लगे कि अरे! यह तो हमारी मंजिल थी ही नहीं।

काम के प्रति हो जुनून

आपमें यदि अपने काम के प्रति गहरा जुनून नहीं है, तो सफलता की राह पर बढ़ना आसान नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो, अपने करियर में ऐसा कुछ तलाशें जो आपको प्रेरित करता हो। आप यदि ऐसा कोई काम करते हैं, जिसे करने पर आपकी आंखों में ऊर्जा और उत्साह भरी चमक आ जाती है तो आपके करियर को उज्वल होने से कोई रोक नहीं सकता।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केसीआर की सरकार जाने वाली है : जी किशन रेड्डी

हैदराबाद। राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के खिलाफ एक मौन क्रांति चल रही है और लोगों को विश्वास हो रहा है कि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की सरकार हार जाएगी और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में आएगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि कुछ गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रसारित होने के बावजूद, भाजपा उम्मीदवारों को क्षेत्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग पार्टी के घोषणापत्र को सकारात्मक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए कि पूर्व एआईसीसी प्रमुख राहुल गांधी के निर्देशों के आधार पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है, रेड्डी ने कहा कि राशि यहां भेजी जा रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सबसे आगे है। यह बीआरएस पार्टी के खिलाफ एक मूक क्रांति की तरह है। लोग बीजेपी के अभियान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

भाजपा नेता दिलीप घोष ने किया राहुल गांधी पर पलटवार

पश्चिम मेदिनीपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी को लेकर आलोचना की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जय के बजाय अडानी जी की जय कहना चाहिए। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, कांग्रेस को सीखना होगा भारत माता की जय कहना, नहीं तो उनका पतन निश्चित है। घोष ने यह बात पश्चिम मेदिनीपुर जिले में छठ घाट पर पूजा करने के बाद कही। भाजपा नेता घोष ने छठ उत्सव पर आज सुबह कंसाबती नदी पर उगते सूरज को अर्घ्य दिया। उसके बाद उन्होंने ढोल भी बजाया और छठ घाट पर आए श्रद्धालुओं को चाय-बिस्किट भी खिलाया। इस मौके पर दिलीप घोष मीडिया से बात करते हुए सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और रोजाना खून-खराबा हो रहा है।

केजरीवाल की सिफारिश को उपराज्यपाल ने ठुकराई

नईदिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मुख्य सचिव के खिलाफ दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को जो रिपोर्ट भेजी थी उस पर विचार करने से इंकार कर दिया गया है जिसको लेकर उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गयी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर विचार करने से इंकार कर दिया है, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। राज निवास के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट पर विचार करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि यह पूरी तरह से मंत्री के पूर्वाग्रह पर आधारित प्रतीत होती है। उपराज्यपाल ने सरकार द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस रिपोर्ट से जारी जांच में मदद मिलने के बजाय उसमें बाधा पैदा हो सकती है।

कांग्रेस की घोषणाएं घोटालों की गारंटी कार्ड : भाजपा

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दल जोर अजमाइश कर रहे हैं। तमाम दलों के वरिष्ठ नेता लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सभी दलों द्वारा लोकलुभावन वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के अभ्यास हस्तम घोषणा पत्र की छह गारंटी पर भाजपा ने चुटकी ली। भाजपा ने हैदराबाद में गांधी भवन के बाहर कांग्रेस की छह गारंटी का मजाक उड़ाते हुए पोस्टर लगा दिया। जिसके बाद से ही कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने है। भाजपा ने कहा, कांग्रेस के द्वारा किए गए सभी वादे घोटालों की गारंटी कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। भूमि अधिकार के मुद्दे पर पोस्टर में टिप्पणी की गई। इसमें कहा गया कि कांग्रेस केवल भूमि अतिक्रमण और 70 फीसदी कमीशनखोरी को बढ़ावा देगी। कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के सभी पद केवल परिवार के सदस्यों को दिए जाएंगे। पिछडे वर्गों से किए गए वादे अभी तक उन तक नहीं पहुंचे। भाजपा ने टिकट बेचने के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए हैं।

मोदी सरकार जनता के साथ ठगी कर रही है : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक्साइज ड्यूटी को लेकर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी राज्यों और देश की जनता के अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस देश की जनता के साथ ठगी कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को मिलने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगभग खत्म कर दिया और उसके जगह पर केंद्र ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1, 2 और सबटैक्स सहित नए एक्साइज ड्यूटी लागू किया है, जिन्हें राज्यों के नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो सारा पैसा अपने खाते में डाल रही है, जिसते कारण राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, भारत सरकार केवल खेल खेल रही है। राज्यों को वितरित की जाने वाली मूल उत्पाद शुल्क लगभग समाप्त हो चुकी है।

राजस्थान चुनाव को भाजपा ने दे दिया है दिलचस्प मोड़

क्या मतदान से ठीक पहले कांग्रेस निकाल पायेगी कोई तोड़?

नईदिल्ली। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कुछ लोक लुभावन योजनाएं शुरू कीं और इनके नाम पर वोट मांगना शुरू किया। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेता अपनी सभाओं में जनता से कहने लगे कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो वह इन योजनाओं को वापस ले लेगी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जायेगा बल्कि उसमें और सुधार कर उसे और जनउपयोगी बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरते हुए यह ऐलान भी कर दिया है कि 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा की जायेगी।देखा जाये तो केंद्र सरकार ने जब उत्पाद शुल्क में कटौती की थी तो अन्य कई राज्यों ने भी वैट की दरें घटा दी थीं जिससे जनता को महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत मिली लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया और यहां के लोग अन्य राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 12 से 13 रुपए ज्यादा देते हैं। देखा जाये तो यह अंतर बहुत ज्यादा है और इससे कांग्रेस के महंगाई से राहत देने के वादे और दावे पर भी सवाल उठता है।राजस्थान की आबादी चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, इसीलिए भाजपा ने जनता को यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालना राज्य में मुश्किल हो गया है, भाजपा ने यह भी याद दिलाना शुरू कर दिया है कि कैसे विपक्षी गठबंधन इंडी के नेता सनातन धर्म और सनातन संस्कृति पर हमला बोल रहे हैं, भाजपा लोगों को यह भी याद दिला रही है कि कैसे 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया गया था।देखा जाये तो चुनाव प्रचार के इस अंतिम दौर में स्थानीय मुद्दे दरकिनार होते जा रहे हैं। आइये आपको सिर्फ आज ही के दिन भाजपा नेताओं की जनसभाओं और संवाददाता सम्मेलन के कुछ अंश बताते हैं जिससे आपके समक्ष स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्थान का चुनाव किस ओर बढ़ चला है। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।

प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी (घमंडिया गठबंधन) सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ये करने देंगे? प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि राजस्थान सरकार की लूट का एक उदाहरण यहां पेट्रोल की कीमतें हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार इन राज्यों से प्रति लीटर 12-13 रुपये महंगा पेट्रोल बेचती है। उन्होंने कहा कि मैं आज राजस्थान को गारंटी देता हूं कि 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार बनने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है और वह दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। मोदी पाली में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ''आज पूरा देश विकसित होने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो उसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।'' उन्होंने कहा ''%दुर्भाग्य से यहां पिछले पांच साल से जो कांग्रेस सरकार रही है, उसने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए परिवारवाद ही सबकुछ है।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में पांच वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर एक बना दिया है।'' मोदी ने यह भी आरोप लगाया ''कांग्रेस व इसके %घमंडिया% साथियों की सोच महिला विरोधी है।'' मोदी ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों से मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, वहां एक स्वर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है- जन जन की है यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार।%%

भाजपा अध्यक्ष का बड़ा बयान

वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान राम नवमी की यात्रा को रोका गया, कांवड़ यात्रा को रोका गया, 300 साल पुराना मंदिर ढहा दिया, 18 से अधिक संतों की हत्या हुई, मंदिरों का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि अब 25 नवंबर को आप इनकी सरकार ढहा देना।

भाजपा प्रवक्ता का हमला

इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने सनातन संस्कृति पर हमला करने का प्रयास किया। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है तबसे कांग्रेस में फैंसी ड्रेस कम्पीटिशन चल पड़ा है। कोई यज्ञ कर रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है।

राजस्थान में सत्ता विरोधी माहौल नहीं : गोविंद सिंह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सीएम पर फैसला आलाकमान के हाथ में

सीकर। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला विधायकों से राय ले कर चुनाव के बाद पार्टी आलाकमान करेगा जो सबको स्वीकार होगा। डोटासरा ने पीटीआई- को दिए गए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा हमारी पार्टी का पहले से एक स्पष्ट रुख है। हम पहले से कभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करते। जो विधायक जीतेंगे, पार्टी आलाकमान उनसे राय लेकर फैसला करेगा जो सबको स्वीकार होगा। हम वह फैसला मानेंगे, पहले भी मानते आए हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चेहरा कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान में भी नाकाम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले डोटासरा ने गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के मतभेदों से जुड़े सवाल पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं के बीच कोई कभी मनभेद नहीं रहा है तथा सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा हमारे बीच कभी मनभेद नहीं रहे। सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में हम जीतेंगे। पूर्व मंत्री डोटासरा सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से वह पिछले तीन बार लगातार निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके खिलाफ कोई माहौल, कोई नाराजगी नहीं है। पहले महंगाई राहत कैम्प में जो 10 गारंटी दी गई थीं, वह प्रभावी हैं। फिर सात गारंटी और दी गईं जो जनता को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता समझ रही है कि 17 गारंटी कांग्रेस ही दे सकती है क्योंकि

भाजपा के पास न कोई दृष्टिकोण है, न कोई गारंटी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा केंद्र के अपने 10 साल के शासन के बारे में ऐसा कोई काम नहीं बता पा रही है जिससे जनता उसे वोट दे। डोटासरा के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं हैं। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री राजस्थान में जितना आ रहे हैं उतना ही भाजपा के प्रति लोगों में विरोध बढ़ रहा है... इस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त है.... मोदी जी का चेहरा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में विफल हो चुका है, अब राजस्थान में भी यही होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बार-बार राजस्थान आना इस बात का प्रमाण है कि उनका स्थानीय नेतृत्व खत्म हो चुका है और उस पर इन्हें भरोसा भी नहीं है। डोटासरा ने उनके और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विमर्श गढ़ने का एक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा, ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई भाजपा के चुनाव लड़ने के हथियार बन गए हैं। मेरे पूरे आवास की तलाशी ली गई, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। यह केवल एक षड्यंत्र है ताकि विमर्श गढ़ा जा सके कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है।

खेल
प्रमुख समाचार

फाइनल में हार पर छलका रोहित शर्मा का दर्द

अहमदाबाद। मिशेल स्टार्क की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेड के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को हुए आइसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को छह विकेट से हराकर लगातार नौवीं जीत के साथ छठी बार विश्व विजेता बना। इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। लगातार 10 जीत के विजय रथ पर सवार होकर फाइनल में पहुंचे भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीद थी। कप्तान रोहित शर्मा पहली बार एकदिवसीय विश्व चैंपियन बनने का सपना संजोये थे, लेकिन पैट कमिंस की टीम ने इन सपनों को साकार नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि क्यों वह विश्व क्रिकेट की शीर्ष टीम है।

भारत के 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हेड की 120 गेंद में चार छक्कों और 15 चौकों से 137 रन की पारी के अलावा मार्नस लाबुशेन (110 गेंद में नाबाद 58 रन, चार चौके) के साथ उनकी चौथे विकेट की 192 रन की साझेदारी से 43 ओवर में चार विकेट पर 241 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारत इस तरह जोहानिसबर्ग में 2003 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का बदला चुकता करने में विफल रहा।वहीं, हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का दर्द भी सामने आया। उन्होंने कहा कि परिणाम भले ही पक्ष में नहीं रहा लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा नहीं रहा। लेकिन मुझे टीम पर गर्व है। ईमानदारी से कहूं तो अगर स्कोर में 20-30 रन जुड़ते तो अच्छा होता। बता दें, टीम को इसी साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने हराया था जबकि 2015 विश्व कप सेमीफाइनल में भी इसी टीम ने उसे शिकस्त दी थी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 139 अंक गिरा निफ्टी 19,700 के नीचे

नईदिल्ली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 139.58 अंक की गिरावट के साथ 65,655.15 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 37.80 अंकों की गिरावट के साथ 19,694.00 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100, बीएसई स्मॉल कैप और निफ्टी आईटी में मामूली तेजी दर्ज की गई। भारतीय शेयर बाजार की आज (20 नवंबर) को सपाट शुरुआत हुई। ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेतों के कारण प्रमुख इंडेक्स ओपेनिंग से ही लाल निशान में दिखे। बीएसई का 30 शेयरों सूचकांक 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 0.19 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में भारती एयरटेल, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति लाभ पाने वालों में से थे।

अनसिक्योर्ड बैंक लोन पर जोखिम भार बढ़ाना सही कदम

नईदिल्ली। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को कहा कि व्यक्तिगत ऋण के लिए नियमों को कड़ा करने का आरबीआई का निर्णय सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। मूडीज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असुरक्षित ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे वित्त संस्थानों को अचानक आर्थिक या ब्याज दर के झटके की स्थिति में ऋण लागत में संभावित वृद्धि करनी पड़ती है। उच्च जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के जरिए से हामीदारी मानदंडों को कड़ा करना ऋण के लिए सही कदम है क्योंकि ऋणदाताओं की नुकसान से निपटने की स्थिति बेहतर करने के लिए उच्च पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता होगी।

बेंगलुरु में तीसरी तिमाही में कार्यस्थल को पट्टे पर लेने की मांग में 28% की गिरावट

बेंगलुरु। बेंगलुरु कार्यालय बाजार चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में प्रभावित हुआ। इस दौरान कार्यस्थल को पट्टे पर लेने की मांग में 28 प्रतिशत की गिरावट आई। कॉरपोरेट जगत की कमजोर मांग के बीच नई कार्यस्थलों को पट्टे पर लेने की दर में भी सालाना आधार पर 25% की गिरावट आई। रियल एस्टेट के सलाहकार वेस्टियन ने यह जानकारी दी। वेस्टियन ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए भारत के शीर्ष सात शहरों की अपनी कार्यालय बाजार रिपोर्ट जारी की। बेंगलुरु में जुलाई-सितंबर तिमाही में कार्यालय स्थल की मांग सालाना आधार पर 28% गिरकर 36 लाख वर्ग फुटा हो गई। यह एक साल पहले समान अवधि में 50 लाख वर्ग फुट थी। बेंगलुरु में नए कार्यस्थलों की मांग सालाना आधार पर 25% गिरावट के साथ 27 लाख वर्ग फुट रही।

टीसीएस ने एएसएक्स के साथ किया समझौता

नईदिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने ऑस्ट्रेलियाई बाजार को अगली पीढ़ी का समाशोधन व निपटान मंच प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति विनिमय एएसएक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टीसीएस की ओर से जारी बयान के अनुसार, एएसएक्स बदलाव को सक्षम करने के लिए बाजार के बुनियादी ढांचे के लिए टीसीएस बीएएनसीएस लागू करेगा। टीसीएस उत्पाद का इस्तेमाल नकद इक्विटी समाशोधन व निपटान के लिए एएसएक्स के मौजूदा मंच को बदलने के लिए किया जाएगा। बीएफएसआई उत्पादों और मंचों के लिए टीसीएस के अध्यक्ष ने कहा, हमारा इस मिशन-महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए चयन, हमारे प्रदर्शन, हमारे उत्पादों में निरंतर निवेश और प्रौद्योगिकी-आधारित दुनिया में बाजार के बुनियादी ढांचा संस्थानों के भविष्य को लेकर हमारे साझा दृष्टिकोण की पुष्टि है।

स्वदेशी के मंत्र ने भारत के आर्थिक विकास को नये पंख लगा दिये हैं

ललित गर्ग

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता को संबोधित करते हुए सतत विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर बल दिया। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वॉकल फोर लॉकल का आह्वान आर्थिक विकास आधार बन रहा है। स्व-भाव एवं स्वदेशी के मंत्र ने आर्थिक विकास को पंख लगाये हैं जिससे अर्थ की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी है। भारत की आर्थिक तरक्की दुनिया को स्तंभित करने लगी है, क्योंकि भारत का घरेलू बाजार ही इतना विशाल है कि भारत को विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक निर्भरता नहीं करनी पड़ रही है। भारत के बाजार से कई देशों का आर्थिक विकास होता रहा है, अब स्वदेश जागरण से देश का अर्थ देश में ही रहने लगा है।

चीन की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से दौड़ी थी और चीन के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का सर्वाधिक योगदान था परंतु आज भारत की आर्थिक प्रगति में घरेलू कारकों एवं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का प्रमुख योगदान है। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि केवल 7 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर को पार कर जाएगा। भारत की 'नीली अर्थव्यवस्था' का

सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 प्रतिशत का योगदान है, जो अवसरों के सागर का प्रतिनिधित्व करता है। तट के किनारे नौ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों, 12 प्रमुख और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों और नौगम्य जलमार्गों के व्यापक नेटवर्क के साथ, भारत महासागर आधारित व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खड़ा है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर (आईएमईसी) सबसे आशाजनक कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है। 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित, आईएमईसी एक मल्टीमॉडल आर्थिक गलियारा है जिसमें शिपिंग, रेलवे, रोडवेज, बिजली केबल, हाई-स्पीड डेटा केबल और एक हाइड्रोजन पाइपलाइन शामिल है। गलियारे का उद्देश्य परिवहन दक्षता को बढ़ाना, रसद लागत को कम करना, आर्थिक एकता को बढ़ावा देना, रोजगार उत्पन्न करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके एक स्वच्छ, सुरक्षित दुनिया में योगदान देना है। भारत चीन से भी आगे निकलकर विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है, बड़ी आबादी को आर्थिक विकास का माध्यम बनाने में सरकार की सूझबूझ एवं योजनाएं कारगर साबित हो रही है। बड़ी आबादी के अनेक तरह के नुकसान हैं तो इसी से भारत में उत्पादों का उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह भारत न केवल उत्पादों के उपभोग का प्रमुख केंद्र बन बन रहा है बल्कि विश्व के लिए एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पूर्व में ही वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आगे आने वाले 10 वर्षों के दौरान आर्थिक क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक स्तर पर सुपर पावर बनने के पीछे भारत के विशाल आंतरिक बाजार, स्व-भाव एवं स्वदेशी का दर्शन मुख्य कारण है। आम जनता में स्व का भाव जगा कर, उनमें राष्ट्र प्रेम एवं स्व-संस्कृति की भावना विकसित करना भी आवश्यक है।

अपनी विदाई और हार की समीक्षा कर रही कांग्रेस: बृजमोहन

रायपुर। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में अब दावों और कयासों का दौर चल रहा है। हार, जीत को लेकर बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। क्योंकि उसे इस बात का आभास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है। जनता बीजेपी के स्वागत के लिए तैयार है, इसलिए कांग्रेस अपनी विदाई और हार की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आभास हो गया है कि वह जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 19 नवंबर को महादेव घाट में छठ कार्यक्रम में था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज और उनका दबा हुआ बोल इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें आभास हो गया है कि वह जाने वाले हैं और बीजेपी सरकार आने वाली है। अग्रवाल ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा बहुमत से आएगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस में सीएम को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस में पहले मुख्यमंत्री के चार दावेदार थे, अब पांच हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी की आस्था पर कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी कोई नई बात नहीं है। हम पिछले 40 साल से छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे लगा रहे हैं। कांग्रेस केवल राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ महतारी का उपयोग करती है।

वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी जिस दिन सुजलाम और सुफलाम होगी , यहां पर अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहां की बच्चियों का जीवन सुरक्षित होगा, उसी दिन छत्तीसगढ़ महतारी खुश होगी। आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लेकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। छत्तीसगढ़ महतारी को फलवित और पुष्पित करना उनका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी अपने आलाकमान को खुश करने में लगे रहते हैं।

मोदी की गारंटी पर भरोसा जताने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का अभार

रायपुर ।छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है।सोमवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मतदान में महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत से साफ हो गया हैं कि, महिलाओं को महतारी वंदन के तहत 12,000 रुपए प्रति वर्ष, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बेटी होने पर डेढ़ लाख रुपए, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, आदि मोदी की गारंटी पसंद आई है और महिलाओं ने उस पर भरोसा जताया है।बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, भाजपा छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है।वहीं कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों से प्रमाण पत्र लेने पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि, भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। और उसकी समीक्षा के लिए ये प्रयास किए जा रहे है।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

जीत की संभावनाएँ साथ

क्रिकेट हमारे देश में खुमार की तरह चलता है। क्रिकेट के प्रति प्रेम के चलते अभी हमने देखा कि एक दिवसीय विश्व कप मैच को देखने के लिए लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके अहमदाबाद की यात्रा की। एक सज्जन बता रहे थे कि जब उन्होंने अपने भतीजे से पूछा कि अहमदाबाद तो जा रहे हो लेकिन वहां सारे होटल बुक हैं। रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी, तो लड़के ने कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं। मैं बीमारी का बहाना करके किसी अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाऊँगा । तो यह जुनून है लोगों के मन में ! दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा जुनून कभी फुटबॉल जैसे गतिशील खेल के लिए नहीं होता। आज भारत का नाम फुटबॉल के मामले में दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारी सरकारों ने कभी फुटबॉल को महत्व दिया ही नहीं। हर कोई क्रिकेट का दीवाना है यही कारण है कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय क्रिकेट के अंतिम मुकाबले में भारत पराजित हो गया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पता नहीं हमने क्या खो दिया है। कल तक जिन खिलाड़ियों को हम सम्मान दे रहे थे, उन खिलाड़ियों को गरियाने लगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला जा रहा था, उसे देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे,तो उसको लेकर तरह-तरह की नकारात्मक बातें लोग करने लगे । गोया मोदी जी की उपस्थिति के कारण हार गए। खेल तो खेल होता है। दो टीम मैदान में उतरेंगी, तो स्वाभाविक है कि कोई एक जीतेगी। और जो टीम जीतती है, नि:संदेह उसका खेल पराजित टीम से तो बेहतर होता ही है। 19 नवंबर के मैच को मैंने भी ध्यान से देखा। जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी, तभी मुझे लगा था भारतीय टीम शायद हार जाएगी । टीम के कप्तान रोहित शर्मा जिस लापरवाह तरीके से खेल रहे थे, उसे देखकर मैंने अपने बेटे से कहा ही था कि देखना, थोड़ी देर बाद यह कैच आउट हो जाएगा। और कुछ देर बाद ही वह कैच आउट ही हुआ। इसके पहले रोहित तीन चार-बार उनके कैच आउट होते-होते बचा था। हमारी भारतीय टीम के बारे में हम सब ने महसूस किया है कि वह शुरुआती मैच तो जबरदस्त खेलती है, जीतती भी है, लेकिन फाइनल मैच में वह कुछ अतिरिक्त तनाव पाल लेती है। दबाव में आ जाती है। इसलिए जैसा खेल उसे खेलना चाहिए, वैसा खेल नहीं पातीम अहमदाबाद के मैच में भी ऐसा ही हुआ। जितने रन बनने चाहिए उससे काफी काम बने। प्राय: शतक जमाने वाले विराट कोहली भी कमाल नहीं दिखा सके। रोहित शर्मा भी। शुभमन गिल तो चार रन बना के पैवेलियन लौट गए। अगर भारतीय टीम 300 से ज्यादा रन बना लेती तो बहुत संभव है ऑस्ट्रेलिया की टीम को पराजित किया जा सकता था । हमारे बॉलरों ने शुरुआत में तो काफी अच्छा खेला। 47 रन तक आस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन लेकिन बाद में वे विफल रहे। ट्रेविस हेड को अंतत आउट नहीं कर पाए, जो मैन ऑफ द मैच बने। जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 137 रन बनाए। अगर हमारे गेंदबाज ट्रेविस् हेड को आउट कर देते तो बहुत संभव है, जीत का सेहरा भारतीय टीम के सर पर बंध जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, खेल तो खेल होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के दमदार खेल ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। छठी बार वह विश्व विजेता बनी। भारत केवल दो बार विश्व चैंपियन बन सका । 1983 में और 1911 में। बहरहाल, आने वाले समय में हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम बेहतर प्रदर्शन करके विश्व विजेता बनेगी। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम क्रिकेट के मोह में फंसे हुए हैं, और धीरे-धीरे इसे सटोरियों का भी खेल बना दिया गया, तब यह जरूरी है कि हम लोग फुटबॉल और हॉकी को भी खूब प्रोत्साहित करें। क्रिकेट खिलाड़ियों पर तो बेहिसाब दौलत बरसती है, लेकिन फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ियों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। अगर हम फुटबॉल खिलाड़ियों को भी महत्व दें, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम भी विश्वस्तर के फुटबॉल खिलाड़ी दे सकते हैं। अंतत: कहूँगा कि एक दिवसीय विश्व कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम के पराजित होने पर एक भारतीय होने के नाते मुझे भी गहरा दुख है। लेकिन अपने ही दो शेरों से अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ कि

आपकी शुभकामनाएँ साथ हैं
क्या हुआ गर कुछ बलाएँ साथ है
हारने का अर्थ यह भी जानिए
जीत की संभावनाएँ साथ हैं।

पुरंदर ने कहा, मेरे कार्यकर्ता मेरे दिल के धड़कन, मुझे जीरो से बना दिया हीरो

रायपुर। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के एक दिन बाद ही रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कार्यकर्ता आभार का आयोजन किया। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल और 22 वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुरंदर मिश्रा ने कहा कि ये कार्यकर्ता मेरे दिल की धड़कन हैं। इन कार्यकर्ताओं ने एक माह के भीतर मुझे जीरो से हीरो बना दिया। उनके प्रयास का प्रतिफल है कि आज पूरे उत्तर विधानसभा के मतदाता मुझसे परिचित हो गए हैं। मिश्रा ने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं का संघर्ष सकारात्मक परिणाम लेकर 3 दिसंबर को सामने आएगा, जिसके बाद क्षेत्र के विकास की रूपरेखा मिलकर बनाएंगे और उत्तर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश के लिए एक मॉडल के तौर पर विकसित करेंगे।

रविवार को भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनावी रण में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यकर्ता आभार बैठक आयोजित किया। जगन्नाथ परिसर में आयोजित इस आभार प्रदर्शन बैठक में बड़ी तादाद में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस आभार प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में इस बार सर्वाधिक चर्चा की सीट उत्तर विधानसभा ही रही है। रायपुर की चारों सीट में भाजपा की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश में 50 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की मेहनत के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है। उनकी मेहनत का प्रतिफल 3 दिसंबर को भव्य विजय जुलुस के तौर पर राजधानी में नजर आएगा।वहीं उत्तर विधानसभा के चुनाव संचालक लोकेश कावड़िया ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पुरंदर मिश्रा को भावी विधायक के तौर पर शुभकामनाएं और कार्यकर्ताओं को अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर बसना से भाजपा प्रत्याशी संपत अग्रवाल ने कहा कि पुरंदर मिश्रा का उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी चुना जाना अप्रत्याशित नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति की कृपा है, और जीत सुनिश्चित है।

महिलाओं का 50 क्षेत्रों में मतदान ज्यादा

आधी आबादी को भाजपा-कांग्रेस की नकदी घोषणाओं ने लुभाया

रायपुर। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। 7 और 17 नवंबर को हुए दो चरणों में मतदान के आंकड़ों के अनुसार, मतदान में कुल एक करोड़ 55 लाख 61 हजार 460 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 77 लाख 48 हजार 612 पुरुष मतदाता और 78 लाख 12 हजार 631 महिला मतदाता शामिल रहीं। वैसे भी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है।

59 प्रतिशत सीटों पर महिला मतदाता ज्यादा: इस चुनाव में करीब 59 फीसदी सीटों पर महिला वोटर्स का वर्चस्व रहा। 53 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इनमें 23 आदिवासी के लिए रिजर्व सीटें हैं, जबकि 2 एससी वर्ग के लिए रिजर्व हैं। शेष 28 सीटें सामान्य वर्ग की हैंबस्तर में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अधिक रहता है जबकि मैदानी इलाकों में महिलाएं अपेक्षाकृत कम मतदान करती हैं

महिला मतदाताओं को नकदी से लुभाया: भाजपा ने महतारी वंदन योजना के तहत एलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक महिला को सालाना 12 हजार रुपये देगी। ठीक अगले दिन कांग्रेस ने घोषणा की कि उनकी सरकार आई तो हर महिला को 15 हजार रुपये सालाना मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ में पारा लुढ़कने के आसार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नवंबर की शुरुआत से ही हल्की ठंड महसूस होने लगी थी लेकिन बीते कुछ दिनों से मौसम स्थिर बना हुआ है. राजधानी रायपुर के लालपुर मौसम केंद्र के अनुमान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा. वही सोमवार को प्रदेश का मौसम ड्राई रहेगा. छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व से हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने के कारण ठंड में थोड़ी कमी आई है. मौसम विज्ञानी के मुताबिक सोमवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. सोमवार और मंगलवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं. अगले तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

गरीबरथ एक्सप्रेस रद्द होने की तिथि में हुआ बदलाव

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य दिनांक 25 नवम्बर 2023 से 04 दिसम्बर 2023 तक किया जाने की घोषणा की गयी थी । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री

गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा । इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों के परिचालन में गतिशीलता आयेगी । प्रभावित होने वाली गाड़ियों का विवरण इस प्रकार है.रद्द होने वाली गाडियां:1) दिनांक 01 दिसम्बर 2023 के स्थान पर यह गाड़ी 30 नवम्बर, 2023 को लखनऊ से रवाना होने वाली गाडी संख्या 12535 लखनऊ-रायपुर गरीबरथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वही दूसरी ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाड़ियों में विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान चलाई जा रही है। इस अभियान के तहत वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों के पैंट्रीकारों सहित यात्री डिब्बों में ले जाए जा रहे किसी भी प्रकार के विस्फोटक और एलपीजी सिलेंडर, केरोसिन स्टोव आदि ज्वलनशील सामानों की जाँचकर व त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

अजय जामवाल की बनी फर्जी आइडी, कार्रवाई की मांग

रायपुर। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर भाजपा थाने पहुंच गई है। सोमवार को प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जेपी चंद्रवंशी ने राजधानी के सिविल लाइन थाने में शिकायत की।उन्होंने कहा कि यह फर्जी अकाउंट राजनीतिक द्वेषवश दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है। जबकि यह फेसबुक अकाउंट जामवाल द्वारा संचालित नहीं किया जाता और इससे उनका कोई भी संबंध नही है। इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर भाजपा के इंटरनेट मीडिया प्रभारी सोमेश पांडेय, रिषी राज पीठवा, रवि मिश्रा मौजूद रहे। भाजपा ने आशंका जताया है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। उनकी आशंका है कि राजनीतिक कारणों से किन्हीं असमाजिक तत्वों के द्वारा उनके नाम का दुरुपयोग कर मैसेंजर से अन्य लोगों को राहुल गुंडिया, गुंडिया आरके नाम से मैसेज किया जा रहा है कि उनका दोस्त संतोष कुमार जो कि सीआरपीएफ में अधिकारी है और अपने घर की फर्नीचर सामाग्री को बेचना चाहता है। ऐसी झूठी, भ्रमित बातें और मिथ्या तथ्य का संचार किया जा रहा है। शिकायत पत्र में आरोप है कि भाजपा की छवि को धूमिल करने का कूटरचित षड्यंत्र किया जा रहा है। पार्टी ने चिंता व्यक्त करते हुए शिकायत की है कि जामवाल भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के अत्यंत जिम्मेदार पद पर पदस्थ हैं। उनकी गरिमा को धूमिल करने के उद्देश्य से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया है। जिससे गलत संदेश जाने की आशंका है।

बाबा तो अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे : केदार गुप्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 होने के बाद परिणाम को लेकर राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज है. राजनीतिक दल अपने-अपने जीत एक दावा कर रहे हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अगले चुनाव नहीं लड़ने की बात पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बयान दिया है. टीएस सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है.

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर भी तंज कसा है. टीएस सिंह देव के सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि टीएस सिंहदेव के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है. कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छग से उखाड़ के फेंक रहे हैं. बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे नहीं, बाबा कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं. हम चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे साथ रहे. भाजपा की सरकार बन रही हैं. अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने मे आनंद आता हैं. कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर केदार गुप्ता ने कहा कि हमलोग तो देख रहे की कांग्रेस में कितना अंतर्कलह है. पार्टी कई टुकड़ों में बट चुकी है. मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छग का एक्जिट पोल है. जो बता रहा कि कांग्रेसी को जनता ने ठुकरा दिया है. ये आपस में भी लड़ हैं. इनका सर्वनाश, सत्यानाश तय हैं.बीजेपी विपक्ष में हैं लेकिन आजतक कोई गंभीर शिकायत नहीं आई।

सैलजा और बैज ने प्रत्याशियों से पूछा- जीत रहे हैं कि नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनो चरण के मतदान के बाद राजनीतिक दलों ने जीत-हार की समीक्षा पूरी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगातार दो दिनों के भीतर प्रदेश के सभी 90 प्रत्याशियों के साथ बातचीत कर सीटों के गणित की जानकारी ली। शनिवार की तरह रविवार को भी सैलजा और बैज ने एक-एक कर सभी प्रत्याशियों से बातचीत की। बताया गया है कि इस दौरान सभी से वोटिंग प्रतिशत से लेकर बूथवार पड़े वोट की जानकारी भी ली। इस दौरान सत्ता और संगठन के नेताओं के सहयोग और विरोध पर भी बातचीत हुई। बताया गया है कि विधायक प्रत्याशियों ने इस दौरान अपने-अपने क्षेत्र के संगठन से जुड़े नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत भी की। कांग्रेस के पदाधिकारी होने के बाद भी दूसरे दल का साथ दिया। पीसीसी चीफ ने ऐसे नेताओं की सूची बनाकर लिखित में शिकायत करने को कहा है।दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मैच देखते हुए प्रत्याशियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भी प्रत्याशियों से जीत-हार के समीकरणों के अलावा कुल सीटों की गणित पर भी प्रत्याशियों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे।

32 कैमरों से ईवीएम की निगरानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दो चरण में 90 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हो चुका है। 90 सीटों में कुल 1,181 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला तीन दिसंबर को होगा।शुक्रवार को हुए दूसरे चरण में मतदान के बाद अब ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है।सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रायपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों के 123 प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो चुके हैं। स्ट्रांग रूम स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में 24 घंटे है। परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कमरों के बाहर पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इनकी पहरेदारी लगातार 16 दिनों तक चलेगी।ईवीएम मशीनों को अलग-अलग कमरों में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक न हो इसके लिए फोर्स के साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी बिल्डिंग की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर, सीढ़ियों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर सीटीटीवी कैमरे की मदद से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पूरी बिल्डिंग में 32 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा।देर रात तक जारी रहा स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखने का सिलसिला शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान के बाद मतदान दल ईवीएम मशीनों के साथ लौटने लगे। सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए है।

बागी न बिगाड़ दे खेल,कुछ सीटें तो हैं जहां दावेदारों में है घबराहट

रायपुर। 3 दिसंबर को परिणाम का इंतजार तो है लेकिन इससे पहले जीत हार को लेकर कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। पार्टी के छोटे बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि जीत तय है चाहे वे कांग्रेस के हो या भाजपा के लेकिन इस बात पर जाकर ठिठक जा रहे हैं कि कितनी सीट पा रहे हैं और कितनी सीट पर गच्चा खा रहे हैं। कुछ सीटों पर बागी प्रत्याशी समीकरण बिगाड़ रहे हैं यह भी सौ फीसदी सच है। जिन्हे कमतर आंकना पार्टी की भूल होगी इसलिए भीतरखाने यहां से चुनाव लडने् वाले भी कहीं न कहीं घबराये हुए हैं कि कहीं जीत छिन न जाए? इसके लिए इंतजार करना होगा परिणाम आने के दिन तक,तब तक

कयास लगने दीजिए। यह भी जान लें कि किन सीटों पर ऐसे बागी थे जो समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

कांग्रेस के बागी ।जशपुर विधानसभा सीट से प्रदीप खेस कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के खिलाफ, सक्ती विधानसभा अनुभव तिवारी प्रत्याशी डा. चरणदास महंत के खिलाफ, जैजैपुर से टेकचंद्र चंद्रा प्रत्याशी बालेश्वर साहू के खिलाफ, पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन शेषराज हरबंश के खिलाफ, पाली-तानाखार से छत्रपाल सिंह दुलेश्वरी सिदार के खिलाफ, लोरमी से सागर सिंह बैस थानेश्वर साहू के खिलाफ, मुंगेली से रूपलाल कोसरे संजीत बनर्जी के खिलाफ, सरायपाली से विधायक किस्मतलाल नंद चातूरी नंद के खिलाफ, रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा कुलदीप जुनेजा के खिलाफ, धमतरी से लोकेश्वरी साहू ओंकार साहू के खिलाफ, बालोद से मीना साहू संगीता सिन्हा के खिलाफ और कसडोल से गोरेलाल साहू संदीप साहू के खिलाफ चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है।

भाजपा के बाग: भटगांव विधानसभा सीट से राम बाई देवांगन भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े के खिलाफ, जशपुर से शिव भगत रायमुनि भगत के खिलाफ, रायगढ़ से गोपिका गुप्ता ओपी चौधरी के खिलाफ, मस्तुरी से चांदनी भारद्वाज डा. कृष्णमूर्ति बांधी के खिलाफ, वैशालीनगर से जेपी यादव और संगीता केतन शाह दोनों प्रत्याशी रिकेश सेन के खिलाफ, गुंडरदेही से आरके राय वीरेंद्र साहू के खिलाफ, रायपुर उत्तर से सावित्री जगत पुरंदर मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ा है।

चुनाव आयोग का चौंकाने वाला खुलासा, 5 राज्यों में 1760 करोड़ से ज्यादा का सामान, कैश और शराब जब्त

रायपुर। पांच चुनावी राज्यों में 1,760 करोड़ रुपए से अधिक की मादक पदार्थ, नगदी, शराब और कीमती सामान जब्त की जा चुकी है. यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दी और दावा किया कि यह सभी चीजें मतदाताओं को लुभाने के लिए थीं. आयोग ने बताया कि 9 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से अब तक की गई जब्ती इन राज्यों में 2018 में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान की गई जब्ती से सात गुना (239.15 करोड़ रुपये) से अधिक है.

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़,

मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं, जबकि राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे. चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया, पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी उम्मीदवारों और दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर प्रलोभन मुक्त चुनाव पर जोर दिया था.

दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के अनुसार, मिजोरम में कोई नकदी या कीमती चीजें जब्त नहीं की गई, लेकिन अधिकारियों ने 29.82 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बरामद किये. चुनाव आयोग ने विभिन्न सेवाओं के 228 अधिकारियों को व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया है. कड़ी निगरानी के लिए 194 विधानसभा क्षेत्रों को ''व्यय संवेदनशील'' सीटों के रूप में चिह्नित किया गया था. आयोग का मानना है कि जब्ती का यह आकड़ा बढ़ सकता है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.